वर्ष : 16 ❖ अंक : 281 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 25 मई 2022

आईएसबी हैदराबाद के आसपास ड्रोन किया गया बैन 3 | सामाजिक रूप से भारत को तबाह करने के मिशन पर बीजेपी : ओवैसी 8

स्वच्छ भारत अभियान बना सबसे प्रभावी जन आंदोलन : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । सिरवानी-चिसोपानी ग्राम पंचायत इकाई द्वारा दोछुम निम्न माध्यमिक पाठशाला में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि तथा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत सोतई कुमार के साथ ही सिक्किम राज्य एवं पूर्व जिले के स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत की विशेष उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बापू के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के सपने को साकार करने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गईं गतिविधियों पर उत्तर-पूर्वीय स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत एवं सिक्किम राज्य और पूर्व जिले के स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत ने प्रकाश डाला।

अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इक्कीसवीं सदी में देश का सबसे प्रभावी जन आंदोलन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। मनुष्य स्वस्थ्य तभी रह सकता है जब वातावरण स्वच्छ हो। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं जिसके कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्ग से आगे आकर इस जन अभियान में अपना योगदान देने की बात कही साथ ही सभी से आह्वान किया कि भारत में इस अभियान को तब तक चलाने की आवश्यकता है जब तक की लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।

उन्होंने सिक्किम को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता जाहिर की कि सिक्किम में आगे बढ़ने की प्रचुर क्षमता है। स्वच्छता सक्किम की संस्कृति और पहचान है और इस सफलता को आगे बरकरार रखना हर सिक्किमवासियों का कर्त्तव्य है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा शिक्षक एवं अभिभावकों को बच्चों में संस्कार और अच्छी आदतें डालने को कहा। पंचायत को निरन्तर कर्म पथ पर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।

रंगारंग कार्यक्रम के साथ पौधरोपण भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिलाधिकारी, गंगटोक (विकास) श्रीमती राधा प्रधान, बीडीओ-टिकेंद्र शर्मा, अधिकारी, ग्रामवासी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यालय के हॉल के निर्माण हेतु पांच लाख रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की।

सत्तारुढ़ दल हताशा की स्थिति में है : कृष्ण खरेल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टी की सरकार ने दो-तीन वर्षों में सिक्किम के लोगों को धोखा देने, ठगने, झूठ बोलने, उनके अधिकारों, सम्मान और गौरव को गिरवी रखने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये बातें एसडीएफ के प्रचार प्रसार उपाध्यक्ष कृष्ण खरेल ने यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही।

उन्होंने कहा कि सिक्किम के लोग एसकेएम सरकार की जनविरोधी और सिक्किम विरोधी गतिविधियों से तंग आ चुके हैं और एसकेएम पार्टी को शव की तरह छोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए सत्तारूढ़ दल निराशा और हताशा की स्थिति में है। उसकी नैतिकता और जिम्मेदारी खो गई है। सिक्किम को उसके जनविरोधी कार्यक्रमों से तबाह किया जा रहा है। आर्थिक अनियमितताओं ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। कानून का राज खत्म होने से राज्य में घोर अराजकता का माहौल है। सिक्किम और सिक्किम के लोगों द्वारा प्राप्त किया गया गौरव अत्यधिक चापलूसी और भौतिकवाद से लगभग नष्ट हो गया है।

श्री खरेल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर जाकर समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उद्योग, कारखाने, सिक्किम की अचल संपत्ति, व्यापार और वाणिज्य आदि सभी बाहरी पूंजीपतियों द्वारा अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार संस्थागत हो गए हैं। विकास कार्य ठप है। महंगाई चरम पर है। बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। आज तक स्कूलों, शिक्षकों, मजदूरों, किसानों और आम जनता की सुरक्षा, सुविधा आदि के लिए कोई योजना लागू नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य के पुराने कानूनों और संवैधानिक अधिकारों को एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। सिक्किम में विकट स्थिति के बावजूद, राज्य सरकार दिल्ली में राज्य दिवस मनाकर सरकारी खजाने को खाली करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने दिल्ली में राज्य दिवस कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को यह बताने का अपना दायित्व भी पूरा नहीं किया है कि वह क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। राज्य और राज्य के लोगों के लिए डरना और संदेह करना स्वाभाविक है कि सरकार का ऐसा कृत्य उनकी पहचान, सुरक्षा और भविष्य के खिलाफ एक गंभीर साजिश है।

उन्होंने कहा कि सिक्किम एक अलग पहचान वाला राज्य है। इस राज्य का अपना इतिहास, गौरव और स्वाभिमान है। संविधान ने इस राज्य को विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया है। इसलिए सिक्किम राज्य दिवस का अपना अर्थ और महत्व है। अपने राज्य में और अपने लोगों के सामने राज्य दिवस मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। हम जनमत से महान देश भारत के नागरिक बने हैं। सिक्किम के लोग देश की अखंडता और संप्रभुता के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। हालांकि, वे अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराओं को लेकर भी उतना ही न सम्मान रखते हैं।

खरेल ने कहा कि एसकेएम पार्टी की बौद्धिक शाखा के प्रवक्ता प्रदेश और प्रदेश की जनता के अपमान से भरे प्रेस बयान देकर काली करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। अपने स्वाभिमान को बंधक रखकर अपमान से भरा प्रेस बयान देना अपने स्वामी भक्त के लिए एक प्रदर्शनी मात्र है। एसकेएम के प्रवक्ता श्री सीपी शर्मा ने न केवल सिक्किम के लोगों का अपमान किया है, बल्कि जैविक गुरु के रूप में जाने जाने वाले विश्व नेता, 25 वर्षों तक सिक्किम के लोगों के मुख्यमंत्री, सिक्किम को एक आधुनिक राज्य में बदलने वाले महान नेता का भी अपमान किया है। राज्य एसडीएफ ने उनके बयान की कड़ी निंदा करती और उनसे अपना बयान वापस लेने और लोगों से तत्काल माफी मांगने की मांग करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवक्ता से तार्किक जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

गांव के लोगों की हरसंभव मदद करना समाज सेवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी : मंत्री अरुण उप्रेती

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । मंत्री अरुण उप्रेती ने एसकेएम पार्टी की सहयोगी संस्था 'समाज सेवा प्रकोष्ठ' के मुख्यालय का उद्घाटन किया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की सहयोगी संस्था समाज सेवा प्रकोष्ठ के मुख्यालय का उद्घाटन आज तादोंग में किया गया। इस अवसर पर प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष रेखा थापा, राज्य स्तरीय मुख्य समन्वयक एसपी मोक्तन एवं प्रकोष्ठ के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

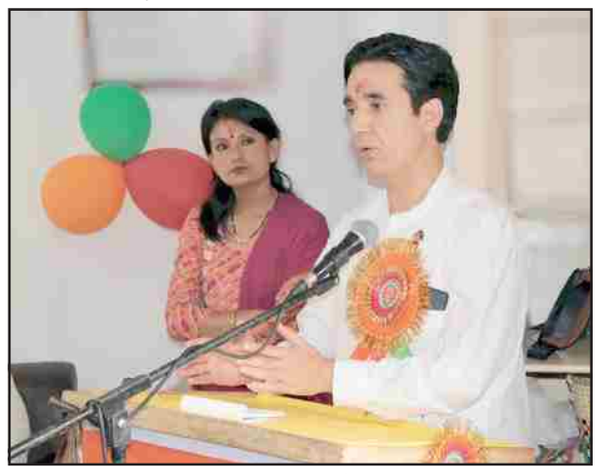

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरुण उप्रेती ने कहा कि एसकेएम पार्टी का मुख्य संगठन समाज सेवा प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ में पार्टी के सभी संगठनों और कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले जाने की क्षमता है। उन्होंने प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सेवा कार्यों की भी खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की हरसंभव मदद करना समाज सेवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है। मंत्री ने प्रकोष्ठ को हरसंभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मिंगमा ल्हमू भूटिया ने कहा कि समाज सेवा प्रकोष्ठ का गठन माननीय मुख्यमंत्री पीएस गोले के आदेश पर लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ में जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन्हें सेवा की भावना से काम करना चाहिए। प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय मुख्य समन्वयक एसपी मोक्तन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सेवा और सहायता के मुख्य उद्देश्य से खोला गया यह प्रकोष्ठ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि आम जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करने का आह्वान किया।

सिक्किम गरीब आवास योजना घरों का लोकार्पण व शिलान्यास

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । दक्षिण सिक्किम के बीएसी तिमी-तार्कू के तिमी टी गार्डन स्थित लामेटार ग्राउंड में आज सिक्किम गरीब आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के उद्घाटन सह शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। राज्य सरकार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री सह क्षेत्र विधायक बेदु सिंह पंथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री गरीब आवास योजना के तहत लामेटार में तिमी टी गार्डन के 20 श्रमिकों के लिये यहां श्रमिक आवास बनाये जायेंगे। परियोजना का कार्यान्वयन आरएमडीडी द्वारा बीएसी तिमी की देखरेख में किया जायेगा।

कार्यक्रम में तिमी टी बोर्ड के चेयरमैन ताशी छिरिंग भूटिया, वाणिज्य व उद्योग विभाग के चेयरमैन व्यासानंद गुरुजी, राज्यस्तरीय उपाध्यक्ष ललित शर्मा, उपाध्यक्ष भीम लाखे के अलावा विभाग अध्यक्ष, तिमी के बीडीओ पी सुब्बा, तिस्ता चरण-5 के उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पौड्याल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इससे पहले तिमी बीडीओ पी सुब्बा ने कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में प्रकाश डाला। वहीं अपने स्वागत भाषण में उन्होंने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए सिक्किम सरकार की इस गरीब कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी।

वहीं कार्यक्रम के दौरान तिमी जीपीयू के विभिन्न इलाकों के 10 जरूरतमंद लोगों को नवनिर्मित आवासों की चाबियां भी प्रदान की गयीं। इसके साथ ही यहां मुख्य अतिथि बेदु सिंह पंथ और तिमी टी बोर्ड चेयरमैन ने यहां ओलोंग टी नामक चाय भी लांच की। कार्यक्रम में पर्यटन व उद्योग मंत्री एवं तिमी टी बोर्ड चेयरमैन ने अपना वक्तव्य भी रखा।

एनएएसी प्रक्रिया में गुणवत्ता समृद्धिकरण एवं ओवरव्यू विषय पर कार्यशाला सम्पन्न

अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 24 मई । इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी), एसजीसी नामची द्वारा 'एनएएसी प्रक्रिया में गुणवत्ता समृद्धिकरण एवं ओवरव्यू' विषयक आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आज स्थानीय एसजीसी ऑडिटोरियम में समापन हुआ। इस दौरान सिक्किम सरकार के एससीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉ. रॉबिन छेत्री और सिक्किम विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. योदिदा भूटिया प्रमुख वक्ता रहे।

डॉ. रॉबिन ने अपने वक्तव्य में मुख्य रूप से एनएएसी एक्रीडेशन प्रक्रिया के आधारभूत ढांचे पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने एनएएसी एक्रीडेशन के 7 कदमों और कॉलेज द्वारा पूरी की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने एक्रीडेशन के दौरान भुगतान किये जाने वाले आवश्यक शुल्क के बारे में भी कहा।

वहीं डॉ. योदिदा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक्रीडेशन प्रक्रिया पर चर्चा की और यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे राज्य की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध के महत्व को बताते हुए एक्रीडेशन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा में सहायक बिंदुओं की जानकारी भी दी। इसके अलावा उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, शिक्षण, मूल्यांकन एवं सीख प्रक्रिया, खोजपरकता, मिश्रित सीख के साथ ही भविष्य की शिक्षा के लिये 'स्वयं' प्लेटफार्म के बारे में भी जानकारी दी।

समापन सत्र में आयोजक दल ने कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु सभी को धन्यवाद दिया। वहीं आईक्यूएसी के संयोजक डॉ. बिष्णु के शर्मा ने प्रिंसिपल डॉ. दीपक तिवारी, वाइस प्रिंसिपल डिकी ओंग्मू लेप्चा और डीन डॉ. डिकी भूटिया को खादा पहना कर स्वागत किया। वहीं दोनों वक्ताओं को भी सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि माहव्यापी मल्टी डिसीप्लीनरी एकेडमिक मीट के एक हिस्से के तौर पर रूसा के प्रायोजन में आईक्यूएसी, नामची द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की गयी थी। इसमें एसजीसी, नामची के सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक सदस्य के अलावा सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, सिक्किम साइंस गवर्नमेंट कॉलेज और सिक्किम बीएड. कॉलेज के फैकल्टी प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. युगल किशोर खनाल ने स्वागत भाषण दिया वहीं आखिर में डॉ. पानू पाजो ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

जिलाधिकारी ने किया भूस्खलन स्थल का दौरा

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 24 मई । जिले के पिपाले और बैगुने के बीच स्टेट हाइवे के आस-पास भूस्खलन स्थल का आज डीसी सोरेंग भीम ठटाल और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उनके अलावा निरीक्षण दल में एडीसी सोरेंग धीरज सुबेदी, एसडीएम सोरेंग रंजन राई, भूमि राजस्व विभाग के आरओ बीबी राई, नया बाजार थाने के एसआई रिंगजिंग लेप्चा के अलावा अन्य अधिकारी शामिल रहे।

इस निरीक्षण के दौरान दल के सदस्यों ने मानसून के दौरान भूस्खलन स्थल के निकट स्थित घरों, आमलोगों को होने वाली असुविधाओं, यातायात की समस्या समेत अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। डीसी ठटाल ने यहां प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह पर ले जाने, ट्रैफिक समाधान हेतु जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बनाने, अधिक तेज गति वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने फ्यूल पम्प के कर्मचारी को साप्ताहिक तौर पर स्टॉक की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को देने का भी निर्देश दिया।

निरीक्षण के क्रम में दल के सदस्यों ने रेशी के डैम निर्माण स्थल का भी एनएचपीसी अधिकारियों के साथ दौरा किया। वहां डीसी ने सम्बंधित अधिकारियों को समुचित निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही रेशी के सुरंग स्थल पर पैदल चलने वालों के लिये पर्याप्त चौड़ाई वाला पथ बनाने को भी कहा। वहीं रेशी सुरंग स्थल पर काम करने वालों श्रमिकों की पहचान हेतु तथा रिकॉर्ड के लिये उन्होंने रेशी थाने में उनके पहचान कागजात भी जमा करवाने को कहा। इसके बाद निरीक्षण दल ने परियोजना स्थल पर डैम के डिसिल्टिंग चैम्बर एवं आस-पास की जगहों का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने एनएचपीसी के साइट मैनेजर से श्रम कानून का कड़ाई से पालन करने को कहा।

श्रमिक सम्पर्क अभियान की लॉचिंग को लेकर बैठक आयोजित

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । श्रमिक सम्पर्क अभियान की लांचिंग को लेकर गंगटोक नगर निगम सभागार में कल एक बैठक हुई जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर एवं सभी काउंसिलरों के अलावा लाल बाजार इलाके के कई दुकानदार भी शामिल रहे।

इस दौरान श्रम सचिव ने सिक्किम शॉप्स एंड कामर्शियल एक्ट, 1983 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सिक्किम लेबर एक्ट, 2021 के तहत श्रमिकों, बिल्डिंग एंड अन्य निर्माण कानून, 1996 के तहत लाभान्वितों के तौर पर कामगारों और लेबर क्लियरेंस सर्टीफिकेट के ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्वयं का ऑनलाइन पंजीकरण करवा कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

वहीं श्रम सचिव ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कामगारों के पंजीकरण में काउंसिलरों एवं पंचातयों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने श्रमिकों को राज्य के श्रम कानून के प्रति जानकारी मुहैया कराने की दिशा में सभी काउंसिलरों से अपने-अपने क्षेत्र में श्रम विभाग की सहायता करने का आग्रह भी किया। उन्होंने राज्य के सभी नियोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं से कामगारों एवं श्रमिकों का पंजीकरण आवश्यक तौर पर करवाने पर जोर दिया।

इस दौरान जीएमसी कमिश्नर ने नगर निगम इलाके की दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शीघ्र ही एक (शेष पृष्ठ ०३ पर)

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), गंगटोक द्वारा छठी राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक कल यहां एक होटल में आयोजित हुई। सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव एससी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आरबीआई, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक केशवन रामचन्द्रन मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं उनके अलावा यहां आरबीआई, गंगटोक के जीएम किशोर परियार, विधि विभाग के सचिव एवं कैग, डीआईजीपी, स्पेशल ब्रांच, सूचना व जनसम्पर्क विभाग के

अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर आरबीआई, गंगटोक के जीएम किशोर परियार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए दोषी एनबीएफसी और अनिगमित निकायों के खिलाफ नियामक प्राधिकरणों एवं एजेंसियों द्वारा ठोस कार्रवाई और कम्पनी कानून के आदेशों के अनुपालन की निगरानी हेतु इस फोरम के गठन की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समिति का उद्देश्य नियामकों के बीच सहयोग, सदस्यों के बीच सूचनाएं साझा करना एवं तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना, ग्राहकों की (शेष पृष्ठ ०२ पर)

कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई : डब्ल्यूएचओ प्रमुख

जिनेवा, 24 मई (एजेन्सी)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक जनरल ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयसस ने सोमवार को कहा कि महामारी खत्म नहीं हुई है। जब हम इससे लड़ना जारी रखते हैं, तब हमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना पड़ता है। 90 प्रतिशत सदस्य राज्यों ने एक या अधिक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान की सूचना दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए घेब्रेयसस ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने प्रदर्शित किया है कि दुनिया को डब्ल्यूएचओ की आवश्यकता क्यों है।

उन्होंने वार्षिक सभा में कहा कि छोटे और बड़े, देखे और अनदेखे तरीकों से, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि यह संगठन बदलाव ला रहा है।

महामारी से पहले, डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया था कि 2023 तक केवल 270 लाख और लोगों को कवर किया जाएगा। 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 730 मिलियन लोगों की कमी है।

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान ने हमें पीछे की ओर भेज दिया है। हमारा अनुमान है कि यह कमी 840 मिलियन तक पहुंच सकती है।

घेब्रेयसस ने यह भी कहा कि सरकारों को अपनी योजनाओं में स्वास्थ्य को प्रमुखता देनी चाहिए।

ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की कोर्ट से मांग

वाराणसी, 24 मई (एजेन्सी)। ज्ञानवापी प्रकरण में वादी राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक अर्जी दाखिल की। इसमें परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली है। उस पर बुधवार को सुनवाई होगी। याची किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री जबकि उनके पति जितेंद्र बिसेन अध्यक्ष हैं।

आदिविश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह और वादी विकास साह व विद्याचंद ने मंगलवार को 80 पेज, 120 पैरा में तीन बिंदुओं पर अदालत आवेदन दिया है। शिवम गौड़, मानबहादुर सिंह आदि अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाय, ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने के लिए सौंप देने का आदेश दें।

इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ कराई जाए। उन्होंने कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट की भी दलीलें दीं। अदालत ने शाम चार बजे याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। बुधवार को सुनवाई होगी। विकास साह व विद्याचंद वाराणसी के ही निवासी हैं।

बहस के दौरान प्रतिवादी जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने बिना नोटिस दिये ही वाद दाखिल करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वादी को कम से कम सभी प्रतिवादियों को वाद के संदर्भ में नोटिस जारी कर सूचित करना चाहिए था। अदालत ने वाद को दर्ज करते हुए वादी को धारा-80 के तहत सभी पक्षकारों को नोटिस देने के लिए वादी को निर्देशित किया।

यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे : नाटो प्रमुख

दावोस, 24 मई (एजेन्सी)। स्वतंत्रता को मुक्त व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन पर आर्थिक निर्भरता में बड़े जोखिम हैं। उन्होंने चीन को अधिनायकवादी सरकार का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन नाटो सैनिकों को वहां भेजकर युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करेगा।

स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि हमने 2014 से यूक्रेन को अपना समर्थन दिया है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। हम समर्थन जारी रखेंगे, लेकिन वहां नाटो सैनिकों को भेजकर हम सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। यह उकसाने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हर सहयोगी सुरक्षित रहे। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक 2022 को संबोधित करते हुए स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने हमें सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन पर आर्थिक निर्भरता के भारी जोखिम हो सकते हैं जिसे हमने ऊर्जा संकट के रूप में देखा है।

नाटो प्रमुख ने कहा कि यह रूस के बारे में है। चीन में भी अधिनायकवादी शासन है। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। मुक्त व्यापार की तुलना में स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है और मूल्यों की रक्षा करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार करने के बहुत लाभ हैं, लेकिन जब 5जी नेटवर्क की बात आती है तो इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध ने यूरोप में शांति भंग कर दी है। रूस के आक्रमण के बाद से हमने अपना समर्थन काफी बढ़ा दिया है। नाटो की मुख्य जिम्मेदारी अपने सहयोगियों की रक्षा करना और इस युद्ध को बढ़ने से रोकना है। नाटो में हमने खुफिया जानकारी एकत्र की और यूक्रेन पर हमला करने के रूस के इरादों के बारे में अपनी जानकारी सार्वजनिक की। 2014 में यूक्रेन पर पहले आक्रमण के बाद से नाटो नजर रख रहा है। जब रूस ने इस साल फिर से यूक्रेन पर हमला किया तो हमने अपना समर्थन बढ़ाया। नाटो क्षेत्र पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमारे पास 1,00,000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का खतरा, एससी पहुंचे आजम खान

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान की अर्जी पर इस सप्ताह सुनवाई को तैयार हो गई है। इस याचिका में यूपी के रामपुर स्थित अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के मंडराते खतरे को चुनौती दी गई है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश के साथ ही रामपुर कलेक्टर को जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन पर किए गए अवैध को मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इससे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाए जाने की संभावना है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आजम खान की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट से मामले की अर्जेंट सुनवाई करने की गुहार लगाई। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह इस मामले को इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी।

10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता खान को जमीन पर अवैधानिक कब्जे से संबंधित एक मामले में जमानत दी थी। यह केस वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर रामपुर को निर्देश देने के साथ ही आजम खान पर विभिन्न शर्तें लगाई हैं।

रामपुर कलेक्टर को यूनिवर्सिटी की भूमि का अभिरक्षक व प्रशासक मानने के साथ इस जमीन को विवाद की जड़ माना गया है। कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वह सिंघन खेड़ा, परगना और तहसील-सदर, जिला रामपुर की 13.842 हेक्टेयर जमीन की नपती कराएं। इसके बाद इसकी चारदीवारी बनवाएं और चारों ओर कंटीले तार लगवाकर इसका भौतिक कब्जा प्राप्त करें। यह आदेश शत्रु संपत्ति प्रशासक मुंबई की ओर से अधिकतम 30 जून 2022 तक करने का निर्देश दिया गया है।

आजम खान कुछ दिनों पूर्व ही जमानत पर रिहा हुए हैं। वह उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के सिलसिले में फरवरी 2020 से यूपी की सीतापुर जेल में बंद थे।

आज 'पाकिसतान के इतिहास में सबसे बड़े जुलूस' की अगुवाई करूंगा : इमरान

पेशावर, 24 मई (एजेन्सी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को पाकिस्तान सरकार के इस्लामाबाद की ओर लंबे मार्च को रोकने के फैसले के बावजूद पार्टी के 'आजादी मार्च' को जारी रखने की योजना बनाई है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, खान ने पेशावर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह बुधवार को 'पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़े जुलूस' का नेतृत्व करेंगे।

पीटीआई अध्यक्ष का भाषण पीटीआई के सदस्यों और नेताओं के खिलाफ देशव्यापी पुलिस कार्रवाई के बाद आया है। एक छापे के दौरान एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने कहा कि वह बुधवार को पीटीआई को लंबे मार्च के साथ आगे नहीं बढ़ने देगी।

खान ने पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह शरीफ परिवार को वही रणनीति अपनाते हुए देख रहे हैं जैसी 1985 से सैन्य तानाशाहों ने अपनाई थी।

उन्होंने कहा, 'सत्ता छोड़ते ही उन्हें लोकतंत्र की याद आती है।'

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी और जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद की ओर मार्च करने पर पीटीआई सरकार ने कोई गिरफ्तारी की थी।

पीटीआई नेता ने पाकिस्तान की न्यायपालिका का आह्वान करते हुए कहा कि अगर अदालतों ने देश में जो कुछ हो रहा है, उसे अनुमति दी तो अदालतों की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और इसकी चुप्पी साबित करेगी कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं है।

जियो न्यूज के अनुसार, इमरान ने कहा, 'हम प्रत्येक अधिकारी और नौकरशाह के नाम नोट कर रहे हैं। नौकरशाही को हमारा संदेश है कि अगर वे अवैध आदेशों का पालन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

पीटीआई अध्यक्ष ने अपने समर्थकों से कहा कि वे 'डर की जंजीरों को तोड़ें' और उदाहरण के तौर पर देखें कि अफगानों ने विदेशी शक्तियों से कैसे लड़ाई की।

खान ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाल सकती, जो उनके समर्थन में इस्लामाबाद जाने को तैयार हैं।

वी का पुणे में चल रहा 5जी परीक्षण

सिलीगुड़ी, 24 मई । वोडाफोन आइडिया और एरिक्सन ने 5.92 जीबीपीएस की पीक डाउनलोड स्पीड का प्रदर्शन करते हुए चल रहे 5जी परीक्षणों के दौरान एक टेक्नोलॉजी माइलस्टोन हासिल करने की घोषणा की। यह पुणे, महाराष्ट्र में अपने 5जी परीक्षणों के दौरान एकल परीक्षण उपकरण पर हासिल किया गया था, जो कि एरिक्सन मैसिव एमआईएमओ रेडियो, एरिक्सन क्लाउड नेटिव डुअल मोड 5जी कोर का उपयोग स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर के लिए मिड-बैंड और हाई-बैंड 5जी ट्रायल स्पेक्ट्रम और एनआर-डीसी (नया रेडियो-दोहरी कनेक्टिविटी) सॉटवेयर के संयोजन पर किया जा रहा है।

अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कल के लिए नई तकनीकों और साझेदारी का लाभ उठाने पर वी के फोकस ने कंपनी को पुणे और गांधीनगर में 5जी परीक्षणों के दौरान 5जी उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि उद्यमों और नागरिकों को स्मार्ट बनाया जा सके। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट, नवंबर 2021 संस्करण के अनुसार, 2027 तक भारत में सभी मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 5जी की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत होने की उम्मीद है। 5जी 2027 तक वैश्विक रूप से सब्सक्रिप्शन द्वारा प्रमुख मोबाइल एक्सेस टेक्नोलॉजी बनने की राह पर है।

5जी से दुनिया भर में सभी मोबाइल सब्सक्रिप्शन का लगभग 50 प्रतिशत होने की उम्मीद है - दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी को कवर करती है और वैश्विक स्मार्टफोन ट्रैफ़िक का 62 प्रतिशत वहन करती है। एरिक्सन में वाइस प्रेसिडेंट और कस्टमर यूनिट वी के चीफ अमरजीत सिंह ने कहा, 121 लाइव नेटवर्क पर हमारे वैश्विक 5जी परिनियोजन के आधार पर, हमें विश्वास है कि हम वी जैसे अपने ग्राहकों को 5जी के लिए अपने नेटवर्क को विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

डिजिटाइज करने का अमेजन का संकल्प

गंगटोक, 24 मई । अमेजन इंडिया ने स्मार्ट कॉमर्स के लॉन्च की घोषणा की - स्थानीय स्टोर को डिजिटल दुकान में बदलने और 2025 तक 1 करोड़ छोटे व्यवसायों को डिजिटाइज़ करने की अपनी प्रतिज्ञा में तेजी लाने के लिए एक नई पहल।

1.5 लाख से अधिक पड़ोस के स्टोर पहले से ही अमेजन.इन का उपयोग करके ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। स्मार्ट कॉमर्स के साथ, स्टोर अब और आगे बढ़ सकते हैं और अपने ऑफ़लाइन संचालन को डिजिटाइज़ कर सकते हैं, अपने वॉक-इन ग्राहकों को इन-स्टोर खरीदारी अनुभव प्रदान कर सकते हैं और सीधे ग्राहकों की सेवा के लिए अपना ऑनलाइन स्टोरफ्रंट बना सकते हैं।

किसी भी आकार के स्टोर अब अपने ग्राहकों को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद अनुभव प्रदान करने के लिए अमेज़ॅन के सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान और बहुत कुछ का लाभ उठा सकते हैं।

स्मार्ट कॉमर्स स्थानीय स्टोरों को बिलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को डिजिटाइज़ करने और अपने ग्राहकों को एक बेहतर इन-स्टोर अनुभव प्रदान करने में मदद करने के लिए समाधानों का पहला सेट जारी करेगा।

इसके बाद क्षमताओं का शुभारंभ होगा जो उन्हें मिनटों में अपना ऑनलाइन स्टोरफ्रंट बनाने और एक साधारण आवाज और चौट-आधारित खरीदारी अनुभव के माध्यम से अपने ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम करेगा।

अमेज़ॅन ने 10 मिलियन एमएसएमई को डिजिटाइज़ करने, भारत से क्यूमिलेटिव एक्सपोर्ट में $10 बिलियन उत्पन्न करने और 2025 तक भारत में 2 मिलियन नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। अमेजन ने हाल ही में उसी समय सीमा में अपनी एक्सपोर्ट प्रतिज्ञा को 10 बिलियन से $20 बिलियन तक दोगुना कर दिया। अमेजन इंडिया में इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के कंट्री मैनेजर मनीष तिवारी ने कहा, पिछले दो वर्षों में, हमने 2020 में उद्घाटन संभव समिट में घोषित किए गए वादों की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

नवीनतम वानप्लस 10आर दो वेरिएंट में

सिलीगुड़ी, 24 मई । ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड वानप्लस ने आधिकारिक तौर पर भारत में नवीनतम वानप्लस 10आर लॉन्च किया है। यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंशन 8100-मैक्स चिपसेट द्वारा संचालित है और इसमें १८० हर्ट्ज़ लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। मीडियाटेक डाइमेंशन 8100-मैक्स 80: बेहतर एआई परफॉर्मेंस देता है क्योंकि इसमें समर्पित मीडियाटेक एपीयू 580 एआई प्रोसेसर है। वानप्लस 10आर 150 डब्ल्यू सुपरवूक एंड्योरेंस एडिशन के साथ 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आता है और यह सुरक्षित फास्ट चार्जिंग के लिए टीयूवी रीनलैंड प्रमाणित है। यह एक्सक्लूसिव बैटरी हेल्थ इंजन का समर्थन करता है जो दो प्रमुख तकनीकों को शक्ति प्रदान करता है - स्मार्ट बैटरी हेल्थ एल्गोरिथम जो अधिकतम चार्जिंग करंट को ट्रैक और नियंत्रित कर सकता है और बैटरी हीलिंग टेक्नोलॉजी जो चार्जिंग साईकल के दौरान इलेक्ट्रोड को लगातार मरम्मत करने की अनुमति देता है। 80 डब्ल्यू सुपरवूक वाले वानप्लस 10आर डिवाइस में 5000 एमएएच की बैटरी है। दोनों संस्करण एक अनुकूलित स्मार्ट चार्जिंग चिप से लैस हैं जो डिवाइस पर चार्जिंग का प्रबंधन करता है और चार्जिंग सुरक्षा की गारंटी देता है।

यह 50 एमपी सोनी आईएमएक्स766, बड़े सेंसर आकार और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ पीछे ट्रिपल कैमरा सिस्टम, 8 एमपी अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 2एमपी मैक्रो कैमरा, 16 एमपी सेल्फी कैमरा, 3डी पैसिव कूलिंग सिस्टम, एंड्राइडओ 12 पर आधारित ऑक्सीजनओएस 12.1, तीन प्रमुख एंड्राइड अपडेट और चार साल के सुरक्षा अपडेटके साथ आता है। 150 डब्ल्यू सुपरवूक एंड्यूरेन्स एडिशन के साथ वानप्लस 10आर और वानप्लस 10आर 80 डब्ल्यू सुपरवूक क्रमश: आईएनआर 43999 और आईएनआर 38999 से शुरू होते हैं। यह वानप्लस.इन, वानप्लस स्टोर ऐप, अमेजन.इन, वानप्लस एक्सक्लूसिव स्टोर्स और पार्टनर आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट, क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये की तत्काल छूट, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के साथ 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई; एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा जियो प्रीपेड प्लान के साथ आईएनआर 7200 के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

गुजरात में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बेटे की भाजपा में एंट्री

अहमदाबाद, 24 मई (एजेन्सी)। गुजरात के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत विधायक डॉ. अनिल जोशीयारा के बेटे केवल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केवल जोशीयारा, राज्य के अरावली जिला स्थित भिलोडा कस्बे में एक कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हुए।

पार्टी की एक विज्ञप्ति के मुताबिक उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने उनके (केवल के) 1300 समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल किया। केवल ने संवाददाताओं से कहा, मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों से खुश हूं। मैं टिकट पाने की किसी उम्मीद के बगैर पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं भिलोडा सीट से भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा।

राज्य विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने की उम्मीद है। डॉ. अनिल जोशीयारा भिलोडा सीट (अनुसूचित जनजाति) से पांच बार विधायक चुने गये थे और वह उत्तर गुजरात में कांग्रेस का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा थे। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उनका मार्च में चेन्नई के एक अस्पताल निधन हो गया, जब राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नैया पार कराने केलिए पाटीदार के बड़े नेता नरेश पटेल को आगे किया जा सकता है। नरेश पटेल को चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा भी बनाया जा सकता है।

मोदी ने टोक्यो में जापान-भारत संघ के अध्यक्ष से मुलाकात की

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी और शिंजो आबे से मुलाकात की। मोरी जापान-इंडिया एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि शिंजो आबे जल्द ही यह पद संभालेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में मोरी के नेतृत्व में जेआईए द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

उन्होंने शिंजो आबे को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दीं और जेआईए द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखने की आशा की।

नेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के व्यापक कैनवास के साथ-साथ शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए भारत और जापान के साझा दृष्टिकोण पर भी चर्चा की।

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई।

1903 में स्थापित जेआईए, जापान के सबसे पुराने मैत्री संघों में से एक है।

इंडियावुड 2022 बेंगलुरु में

गंगटोक, 24 मई । नूर्नबर्ग मेस्से इंडिया द्वारा आयोजित, इंडियावुड का १ष्वां संस्करण (एशिया में वुडवर्किंग और फर्नीचर निर्माण उद्योग के लिए सबसे प्रासंगिक कार्यक्रम) 2 से 6 जून तक बैंगलोर इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर, बेंगलुरु में होने जा रहा है। पांच दिवसीय कार्यक्रम में नवीन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाएगी और नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

कारपेंटरी, स्किलिंग, इनोवेशन, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में नवीनतम वैश्विक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करके, इंडियावुड 2022 का लक्ष्य भारतीय फर्नीचर निर्माण और वुडवर्किंग इंडस्ट्रीको 2025 तक 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षमता तक पहुंचाना है और भारत को शीर्ष फर्नीचर निर्माण में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद करना है। आर्गनाइज्ड फर्नीचर इंडस्ट्री के भी 2025 तक एक अरब डॉलर के माइलस्टोन तक पहुंचने की उम्मीद है। एक ज्ञान साझा करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में, इंडियावुड अग्रणी इंडस्ट्री संघों द्वारा आयोजित नवीनतम रुझानों और नवाचारों के साथ-साथ फर्नीचर और फिटिंग स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्किल डेवलोपमेंट कार्यक्रमों पर कई सेमिनार आयोजित करेगा।

जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, मलेशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, ताइवान और गैबॉन सहित अन्य देशों के पवेलियन के साथ, पांच दिवसीय कार्यक्रम में नवीन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की जाएगी और नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

वी ने लॉन्च किया 'वी हीरो अनलिमिटेड कैंपेन'

सिलीगुड़ी, 24 मई । लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वी ने एक और अनूठे प्रस्ताव 'डेटा डिलाइट' के साथ 'वी हीरो अनलिमिटेड कैंपेन' शुरू किया है। वी हीरो अनलिमिटेड पोर्टफोलियो में अन्य अनूठे लाभ भी शामिल हैं जैसे कि 12 बजे से सुबह 06 बजे तक अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर।

वी ने पोर्टफोलियो के तहत अधिक रिचार्ज पैक पेश किया हैं। वी हीरो अनलिमिटेड पैक प्रीपेड उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले डेटा कोटा एक्सहाशन की सामान्य चिंता का वान-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए संरचित हैं। वी ने एक उच्च डेसिबल एटीएल कैंपेन थीम - 'सिरफनामकानाहिंकामका अनलिमिटेड' लॉन्च किया है। लोकप्रिय अभिनेता विनय पाठक की विशेषता के साथ, के वी कैंपेन की योजना ८ सप्ताह के लिए है और इस अद्वितीय श्हीरो अनलिमिटेड प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए, टीवी, डिजिटल और ओओएच जैसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ ग्राउंड एक्टिवेशन कार्यक्रमों पर कार्रवाई की जाएगी।

उपयोगकर्ता इन लाभों का लाभ सुबह 12 बजे से सुबह 06 बजे तक, वीकेंड डेटा रोलओवर, डेटा डिलाइट से उठा सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने दैनिक डेटा कोटा के अलावा 2जीबीए क्स्ट्रा डेटा/मंथ अनलॉक करने में मदद करता है।

उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर से या वी ऐप के माध्यम से 121249 डायल करके डेटा डिलाइट को अनलॉक कर सकते हैं। वी हीरो अनलिमिटेड पैक 299 रुपये और उससे अधिक डेली डेटा कोटा पैक के रिचार्ज के साथ शुरू होते हैं। वी ने हीरो अनलिमिटेड पोर्टफोलियो के तहत 359 रुपये, 409 रुपये और 475 रुपये में उच्च दैनिक डेटा कोटा के साथ नए रिचार्ज पैक भी जोड़े हैं।

आईएसबी हैदराबाद के आसपास ड्रोन किया गया बैन

हैदराबाद, 24 मई (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्थान के दौरे के मद्देनजर साइबराबाद पुलिस ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के आसपास रिमोट-नियंत्रित ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान उड़ाने पर रोक लगा दी है।

साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट सीमा के अधिकार क्षेत्र में आईएसबी, गाचीबोवली और गाचीबोवली स्टेडियम से 5 किमी के दायरे में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर और माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी। यह पाबंदी 25 मई से रात 12 बजे से 26 मई शाम 6 बजे तक लागू रहेगा।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद, (जो साइबराबाद के प्रभारी आयुक्त भी हैं) ने मंगलवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188, धारा 121, 121 (ए), 287, 336, 337, 338 आदि के तहत दंडनीय होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि, 'खुफिया एजेंसियों को पैरा-ग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट आदि के उपयोग से आतंकवादी/असामाजिक तत्वों द्वारा हमलों की संभावना के बारे में इनपुट प्राप्त हुए हैं और शांति भंग और सार्वजनिक शांति भंग होने की पूरी संभावना है और उस कारण मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति के लिए भी गंभीर खतरा है।'

अधिसूचना में गृह मंत्रालय, आईएसआई डिवीजन / वीआईपी सुरक्षा, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक ज्ञापन का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आतंकवादी / असामाजिक तत्व पैरा ग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट आदि के माध्यम से हमले कर सकते हैं और यह कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण और फोटोग्राफी के लिए हवाई ऑश्य प्राप्त करने के लिए रिमोट नियंत्रित ड्रोन का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य पुलिस अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस राज्य की राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसर से पांच किमी के दायरे और रणनीतिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास दो किमी के घेरे से घिरे क्षेत्र में ऐसे हवाई ख़्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगाएगी।

प्रधानमंत्री संस्थान के 20वें वार्षिक दिवस समारोह और बिजनेस स्कूल के 2022 के स्नातकोत्तर कार्यक्रम वर्ग के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए आईएसबी का दौरा करेंगे।

इस बीच, साइबराबाद पुलिस ने 26 मई को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर आईएसबी के आसपास के कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधों की भी घोषणा की।

पुलिस ने गाचीबोवली स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) जंक्शन, आईआईआईटी जंक्शन से विप्रो जंक्शन, आईआईआईटी जंक्शन से गचीबोवली के बीच स्थित कार्यालयों को सलाह दी है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने काम के समय को तदनुसार कम करें या घर से अपना काम करें।

यात्रियों को यातायात की भीड़ से बचने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

यूपी में बड़े पैमाने पर इसी सप्ताह मिलेंगे रोजगार, योगी सरकार ने बनाया हर जिले के लिए प्लान

लखनऊ, 24 मई (एजेन्सी)। यूपी की योगी सरकार ने हर हाथ को काम के संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार किया है। सेवायोजन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रति माह रोजगार मेले को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से यूपी के हर जिले में प्रत्येक सप्ताह रोजगार मेला आयोजित होगा।

योगी सरकार की इस मुहिम से रोजगार मेले में सभी रोजगार-स्वरोजगार सृजन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर इस आयोजन के लिए नोएडा और गाजियाबाद को अलग से चुना गया है।

यूपी में एक अप्रैल से 23 मई तक 197 लघु एवं वृहद रोजगार मेले में 13,811 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। विभाग की ओर से 31 मई तक 20,204 बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 265 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं।

इस वृहद रोजगार मेले का आयोजन लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, बस्ती, गाजियाबाद, झांसी, बांदा, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गौतमबुद्धनगर में किया जा रहा है। ये रोजगार मेले 24 मई से 30 मई तक आयोजित किए जाएंगे। इस मेले में सभी रोजगार सृजन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाकर संबंधित विभाग द्वारा रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिस के माध्यम से इससे जुड़े कार्यक्रमों का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा। प्रशासनिक विभागों के तहत सभी निदेशालय, निगम, बोर्ड और आयोग इत्यादि से संबंधित विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

इनके माध्यम से सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूपों पर अपनी सूचना उपलब्ध करायी जा रही है। सरकारी विभागों और उनसे अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर लगाने के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in की मदद ली जा रही है।

जेल में आम कैदियों वाला खाना नहीं खाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कोर्ट ने दी स्पेशल डाइट की अनुमति

पटियाला, 24 मई (एजेन्सी)। रोडरेज के एक मामले में सजायाफ्ता पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला सेंट्रल जेल में हैं। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसमें सामने आया कि उन्हें फैटी लीवर की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें लो फैट और फाइबर फूड खाने की सलाह दी है। उनका डाइट ख़्लान आज पटियाला की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें स्पेशल डाइट दिए जानें की अनुमति दे दी है।

डॉक्टरों ने सिद्धू को सलाह दी है कि वह अपना वजन कम करें। सिद्धू ने जेल में स्पेश फूड के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास याचिका दी थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें अस्पातल ले जाने और जांच कराने का आदेश दिया था। जांच में लीवर में इन्फेक्शन और फैटी लीवर पाया गया। अब सिद्धू के लिए जेल प्रशासन ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है जो कि उनका डाइट प्लान तैयार करेगा।

नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है। हालांकि अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि गेहूं से एलर्जी होने का कोई आधार नहीं है। हालांकि वजन कम करने के लिए अगर गेहूं का कम इस्तेमाल होगा तो भी ठीक रहेगा।

वहीं राजेंद्र अस्पताल के आहार विशेषज्ञ का कहना है कि बोर्ड ने सिद्धू के लिए सूप, ककड़ी, चुकंदर, जूस और हाई फाइबर फूड की सिफारिश की है। गेहूं के विकल्प के रूप में उन्हें बाजरे की रोटी खाने की सलाह दी गई है।

बता दें कि 1988 के रोडरेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुनाई है। बहस और हाथापाई के बाद एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले कोर्ट ने सिद्धू पर केवल 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल कैद की सजा सुना दी।

बिहार में नकली शराब पीने से 4 दिनों में 8 लोगों की जान गई

पटना, 24 मई (का.सं.)। बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में पिछले चार दिनों में संदिग्ध नकली शराब पीने से आठ लोगों की मौत हो गई है। गया में मंगलवार को शराब पीने से जहां तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य आठ बीमार हो गए, वहीं औरंगाबाद में पिछले तीन दिनों में पांच लोगों की मौत हो गई।

गया में मृतक के परिवार ने दावा किया कि उन्होंने सोमवार को एक शादी समारोह के दौरान शराब पी थी।

मृतकों की पहचान अमर पासवान (26), राहुल कुमार (27) और अर्जुन पासवान (43) के रूप में हुई है। ये लोग जिले के आमस थाना क्षेत्र के पथरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने देशी शराब पी।

कुछ घंटों के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।

उन्होंने उल्टी, पेट दर्द और धुंधली दृष्टि की शिकायत की। उन्हें आमस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में ले जाया गया, जहां अमर पासवान और अर्जुन पासवान की मौत हो गई, जबकि राहुल कुमार को मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

इस समय एक व्यक्ति मगध मेडिकल कॉलेज में, जबकि अन्य सात आमस पीएचसी में भर्ती हैं।

पुलिस इस घटना पर चुख़्पी साधे हुई है, लेकिन पथरा गांव में छापेमारी की है।

नकली शराब से गया के अलावा, पिछले तीन दिनों में पड़ोसी औरंगाबाद जिले में पांच लोगों की जान चली गई और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावा गांव में सोमवार रात तीन लोगों की रहस्यमय हालात में मौत हो गई, जबकि दो अन्य की शनिवार को मौत हो गई थी।

मृतकों की पहचान खिरियावा गांव के शिव साव, शंभू ठाकुर, अनिल शर्मा के रूप में हुई है। अन्य दो रानीगंज गांव के रहने वाले थे, जिनकी शनिवार को मौत हो गई।

अनिल शर्मा के रिश्तेदारों ने दावा किया कि उन्होंने पंडरिया मोड़ में शराब पी थी, जबकि शिव साव और शंभू ठाकुर के परिजनों ने कहा कि उन्होंने सोमवार शाम को पासी इलाके में ऐसा किया।

घर लौटने पर उन्होंने बेचैनी की शिकायत की और उन्हें मदनपुर के सामान्य स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उन्हें सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

शेरघाटी के एक निजी अस्पताल में बबलू ठाकुर और भोला विश्वकर्मा का इलाज चल रहा है।

औरंगाबाद जिले के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने दावा किया कि जिला पुलिस के पास मौतों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। मिश्रा ने कहा, 'मृतकों के परिवार ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। हमें पता चला है कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। फिर भी, पुलिस सटीक कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है।'

सेना में तिब्बती बच्चों शामिल करने की तैयारी में चीन

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। चीन की सेना में तिब्बतियों की भर्ती में तेजी आई है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार चीनी सेना में तिब्बतियों का 16 फीसदी ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। तिब्बतियों की संख्या सेना में बढ़ाने को लेकर चीन कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना तिब्बती बच्चों को शुरू से ही सेना के लिए तैयार भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 4000 से ज्यादा तिब्बती युवाओं और 400 युवतियों को इस साल चीनी सेना पीएलए में भर्ती के लिए चुना गया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में तकरीबन 500 तिब्बतियों को सेना में भर्ती किया गया। इसमें 250 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ये भर्तियां दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच की गई हैं।

जिस तरह से चीन अपनी सेना में तिब्बतियों की भर्ती बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है उससे एक्सपर्ट्स को लगता है कि चीन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (एसएफएफ) के जवाब में यह कदम उठा रहा है। दो साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में जब चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में काफी आगे तक आ गया था। तब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पैंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची अहम चोटियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर ला दिया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारत में रहने वाले तिब्बती सैनिक हैं, जो उस भौगोलिक परिस्थियों के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। जबकि चीनी सैनिकों की वहां की चुनौतियों में हालत खराब हो गई थी।

अब चीन एलएसी के पास के तिब्बती गांवों को अपनी रणनीति में शामिल कर रहा है। चीन पहले ही तिब्बत के इलाके में मंदारिन भाषा को प्राथमिक भाषा के तौर पर स्कूलों में लागू कर चुका है। हाल ही में चीनी सेना ने एलएसी से लगने वाले नागरी प्रांत के 6 से 9 साल के करीब 120 बच्चों को बोर्डिंग में भेजने के लिए चुना है। इनमें लड़के- लड़कियां दोनों शामिल हैं। इन्हें मैंडेरिन भाषा सिखाने के अलावा आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। 10 से 18 साल के बच्चों को शिकान्हे मिलिट्री कैंप में मैंडेरिन, बोधी और हिंदी भाषा की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। पहले चरण में चीनी सेना 11 वीं और 12 वीं के बच्चों को प्रशिक्षण देगी। दूसरे चरण में 12 वीं पास स्टूडेंट 3 से 5 साल तक पीएलए में सेवा देंगे। तीसरे चरण में युवाओं को पीएलए में भर्ती के लिए चीनी सरकार वैकल्पिक मुफ्त उच्च शिक्षा भी देगी।

राज्य स्तरीय समन्वय .....

सुरक्षा सुनिश्चित करना, पारस्परिक हित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की समीक्षा और सुविधा प्रदान करना आदि भी है।

कार्यक्रम के उद्घाटन वक्तव्य में आरबीआई, कोलकाता के आरडी ने संयुक्त फोरम के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए ऐसी बैठकों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संदिग्ध संस्थानों द्वारा अवैध जमा की रोकथाम हेतु एसएलसीसी द्वारा गठित आरबीआई की 'सचेत पोर्टल' के बारे में भी जानकारी प्रदान की। वहीं सीआईडी के एसपी एम थापा ने राज्य में पंजीकृत साइबर अपराधों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों के बारे में शिकायत दर्ज करवाने हेतु नेशनल हेल्पलाइन नम्बर 1930 के बारे में भी जानकारी दी।

इस दौरान मुख्य सचिव ने संदिग्ध संस्थानों द्वारा जमा की अनाधिकृत स्वीकृति की निगरानी हेतु सीआईडी, आईजी के नेतृत्व में एसएलसीसी की एक सब-कमिटी गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि संदिग्ध संस्थाओं द्वारा अनधिकृत जमा को रोकने के लिए आमलोगों के बीच जागरुकता आज की आवश्यकता है और इसके अनुसार उन्होंने आरबीआई, राज्य सरकार, सेबी और आरओसी को जागरुकता फैलाने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी।

श्रमिक सम्पर्क अभियान .....

संयुक्त सर्वेक्षण करवा कर कर्मचारियों की संख्या जानने एवं श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इलाकों में नेपाली भाषा में श्रम कानून से सम्बंधित बैनर एवं होर्डिंग लगाने का भी सुझाव दिया।

40 साल बाद शिमला में होगी एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

शिमला, 24 मई (एजेन्सी)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 40 साल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तीन दिनों तक जारी रहेगी। 27 मई से शुरू होने वाली इस बैठक में 468 छात्र कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और आगामी एक वर्ष का रोडमैप तैयार करेंगे।

इस दौरान चार प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे, जिनमें शिक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे।

राज्य पुलिस पेपर लीक मामले में एबीवीपी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

एबीवीपी की राष्ट्रीय महासचिव निधि त्रिपाही ने मांग की कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं की भूमिका और एक युवा अन्य लोगों को रोजगार कैसे प्रदान कर सकता है, इन सब पर मंथन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक से पहले 25 मई को शिमला में एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें छात्रों के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

26 मई को मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

15-18 आयुवर्ग के 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को कोविडरोधी टीके के पहली खुराक मिली : मांडविया

राजेश अलख

नई दिल्ली, 24 मई। देश में 15 से 18 साल के आयुवर्ग के 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को कोविडरोधी टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सुबह सात बजे तक भारत में कोविडरोधी टीके की दी जा चुकी खुराक की कुल संख्या 192.52 करोड़ से अधिक थी।

देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च को शुरू किया गया था और अब तक इस आयु वर्ग के 3 करोड़ 30 लाख से अधिक किशोरों को पहली खुराक दी जा चुकी है।

भारत ने 3 जनवरी से 15-18 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू किया। अब तक इस आयु वर्ग के 5 करोड़ 92 लाख लाभार्थियों को पहली खुराक दी जा चुकी है।

मांडविया ने ट्वीट किया, युवा भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के 80 प्रतिशत से अधिक युवाओं ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक प्राप्त की है।

देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल दो फरवरी से शुरू हुआ था।

बाद में टीकाकरण अभियान का दायरा चरणबद्ध तरीके से बाकी आबादी के लिये बढ़ाया गया।

Sikkim Housing and Development Board
Awas Bhawan, Church Road,
Gangtok, East Sikkim

EXPRESSION OF INTEREST

Construction of Multi-Level Car Parking cum Shopping Complex at Boomtar, Namchi, South Sikkim

On Design, Built, Finance, Operate Transfer (DBFOT) mode

The Sikkim Housing and Development Board (SH&DB), invites Real Estate Developers with sound Financial background and Private sector entities having experience in development/construction and management of community oriented infrastructure projects, either as a single entity or as a consortium (maximum of 6 members in a consortium) to undertake the project "construction o Multi-Level Car Paring cum shopping complex at Boomtar, Namchi, South Sikkim on Design Built Finance Operate Transfer (DBFOT) mode, within one month of publication of this Notice.

The details are as under.

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the Work	Development of Multi Level Car Parking cum Shopping Complex at Boomtar, Namchi, South Sikkim.
2.	Website	www.shdb.nic.in
3.	Location	Boomtar, Namchi, South Sikkim.
4.	Area	0.53 Acres
5.	Address for Correspondence and Submission of EOI Response	Sikkim Housing and Development Board, Awas Bhawan, Church Road, Hungry Jack, Gangtok, East Sikkim
6.	Contact Nos.	9434022180 7639876614

Under Secretary (Adm.)
Sikkim Housing and Development Board

R.O. No.: 35/IPR/PUB/Classi/2223, DT.: 24.05.2022

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR TEESTA MORNING

Draw No:78 DrawDate on:24/05/22

1st Prize ₹1 Crore/- 76A 04797

Cons. Prize Rs.1000/- 04797 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

03718 11147 22271 25311 26592 28528 49031 56539 82537 85723

3rd Prize ₹450/-

0852 3547 3816 4789 5109 5840 6678 7262 9788 9808

4th Prize ₹250/-

0245 1249 2079 2992 4233 5583 6272 6275 6740 8002

5th Prize ₹120/-

0007 0147 0233 0336 0337 0540 0612 0633 0665 0670
1020 1258 1309 1402 1409 1415 1431 1439 1895 2064
2247 2533 2608 2973 2978 3047 3142 3198 3215 3397
3422 3658 3719 3771 3988 4083 4126 4240 4243 4277
4370 4573 4622 4655 4701 4755 4783 4799 4840 5241
5248 5348 5407 5665 5924 5956 6132 6199 6208 6284
6506 6560 6599 6800 6854 6957 7067 7127 7219 7248
7319 7341 7350 7383 7473 7510 7620 7707 7765 7840
7941 7989 8046 8061 8110 8199 8365 8375 8404 8645
8766 9429 9539 9546 9569 9597 9638 9748 9992 9999

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR PARROT EVENING

Draw No:178 DrawDate on:24/05/22

1st Prize ₹1 Crore/- 63A 24660

Cons. Prize Rs.1000/- 24660 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

15748 26862 37932 45060 54400 62341 66072 75631 92059 95139

3rd Prize ₹450/-

1122 1323 3232 3694 4051 4270 7234 7301 7331 9832

4th Prize ₹250/-

0047 0469 1910 1932 3314 3627 5276 5608 8477 9921

5th Prize ₹120/-

0008 0029 0092 0129 0154 0192 0195 0312 0414 0458
0534 0599 0642 0723 0794 0925 0971 1117 1142 1163
1191 1293 1350 1369 1380 1463 1533 2200 2206 2285
2289 2298 2330 2358 2423 2772 2784 2887 3164 3203
3245 3396 3634 3676 4043 4210 4262 4265 4353 4449
4472 4577 4637 4678 4916 4943 5088 5101 5168 5211
5361 5379 5388 5430 5461 5474 5573 5623 5660 5752
5814 5912 6194 6258 6338 6343 6371 6540 6887 7030
7195 7311 7347 7573 7891 8402 8940 8966 9000 9080
9291 9359 9403 9408 9472 9481 9624 9645 9979 9989

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR MOON TUESDAY

Draw No:78 DrawDate on:24/05/22

1st Prize ₹1 Crore/- 92B 95930

Cons. Prize Rs.1000/- 95930 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

01278 11167 26845 29583 37936 55630 77247 77656 80156 92149

3rd Prize ₹450/-

0841 1263 2217 2673 3581 7638 8434 8913 9015 9394

4th Prize ₹250/-

1936 3333 4504 5144 6193 6302 7721 7751 8100 8341

5th Prize ₹120/-

0091 0157 0194 0212 0248 0253 0410 0561 0906 1134
1165 1384 1489 1786 1948 1960 2001 2088 2302 2340
2371 2373 2388 2406 2462 2585 2595 2907 2999 3070
3163 3167 3220 3225 3234 3357 3507 3574 3648 3719
3906 4009 4139 4548 4793 4935 5206 5260 5463 5756
5964 6114 6201 6352 6437 6447 6464 6604 6637 6996
7115 7149 7195 7234 7452 7610 7679 7804 7848 7909
8174 8198 8223 8277 8285 8289 8292 8388 8424 8430
8554 8566 8684 8706 8719 8752 8923 9018 9043 9098
9110 9170 9177 9180 9190 9218 9220 9224 9907 9996

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

और अब मंकी पॉक्स

पहले महामारी और फिर युद्ध से उपजे मुश्किलात झेलती दुनिया के सामने मंकी पॉक्स के रूप में एक नई चुनौती आ गई है। विभिन्न देशों में इसके सौ से ज्यादा मामलों की पुष्टि होने के बाद इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। एक सप्ताह पहले तक इसके मामले इतने कम थे कि इसे किसी तरह का खतरा नहीं माना जा रहा था। मगर पिछले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के साथ-साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम सहित 12 देशों में इसके मरीज पाए जाने की पुष्टि हो गई। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने कहा है कि कुछ दिनों में इसके और भी मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि यह कोई नई बीमारी नहीं है। अफ्रीकी देशों में इसके हजारों मामले हर साल सामने आते हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब अफ्रीका से बाहर इतने बड़े इलाके में इसका प्रसार देखा जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण का मतलब है कि यह पिछले कुछ समय से फैल रहा होगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। राहत की बात यह है कि अभी तक इन देशों में इस संक्रमण से किसी की मौत होने की खबर नहीं है। अफ्रीकी देशों के जिन इलाकों में यह बीमारी आम रही है वहां भी ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं।

औसतन दस मामलों में एक मौत देखी जाती है। मगर स्मॉल पॉक्स परिवार के इस वायरस का अचानक विभिन्न महादेशों में फैलाव कैसे हो गया यह गुत्थी वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि कहीं इस वायरस ने अपना रूप तो नहीं बदला है। अगर ऐसा हुआ होगा तो नए वेरिएंट के रूप में इसके लक्षण, संक्रमण की क्षमता वगैरह में भी परिवर्तन संभव है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारी इस संभावना का पता लगा रहे हैं कि क्या सेक्स के जरिए भी इसका संक्रमण होता है? यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो जाने के बाद अब उसके टीके का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए संभव है कि इस वायरस के लिए तेजी से फैलना पहले के मुकाबले आसान हो गया हो। इन तमाम आशंकाओं के बीच भी घबराहट की स्थिति न बने इसके लिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अभी भी मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले बहुत कम हैं और इनके आम लोगों के बीच फैलने की गुंजाइश भी कम ही बताई जाती है। लेकिन एक बात तो यह कि ब्रिटेन में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है यानी ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमित व्यक्ति के अफ्रीकी देशों से आने वाले किसी शख्स के साथ संपर्क में आने की कोई बात नहीं है। दूसरे, इस वायरस के बारे में अब भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। इसलिए किसी भी सूरत में सावधानी नहीं छोड़ी जा सकती।

सवाल उठाने वाले कौन हैं?

अवधेश कुमार

यह कहना ठीक नहीं है कि ज्ञानवापी, कुतुबमीनार, मथुरा ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल आदि विवादों के कारण देश में वातावरण संतप्त हुआ है।

केंद्र में नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेशों में भाजपा सरकार आने के बाद लगातार ऐसे विषय उभरते रहे हैं और भिन्न रूप में हम इस तरह का माहौल देखते आ आ रहे हैं। वैसे इन चारों मामलों की सच्चाई यही है कि पार्टी के स्तर पर भाजपा ने इन्हें सतह पर नहीं लाया है।

न्यायालय में आम लोग इन मुद्दों को लेकर गए थे। कुतुबमीनार पर भी जो प्रदर्शन हुए उनमें अलग-अलग संगठनों या समूहों के लोग शामिल थे, लेकिन हिंदुत्व और ऐसे विवादित धर्मस्थलों का मामला जब भी उठेगा तो विरोधी भाजपा और संघ का ही नाम लेंगे और यह अस्वाभाविक नहीं है। सत्ता के साथ-साथ संगठन के रूप में भी सर्वाधिक शक्ति इन्हीं के पास है और ऐसे मुद्दे उठाने वालों को हर तरह का सहयोग इनकी ओर से प्रत्यक्ष परोक्ष मिलता भी है। किंतु हम न भूलें कि पूरा मामला न्यायालय के फैसले से ही निर्धारित होता है। इस समय भी ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह मस्जिद का मामला न्यायालयों के आदेशों के कारण ही यहां तक पहुंचा हुआ है। यह तो संभव नहीं कि कोई मामला तथ्य और तर्क के आधार पर न्यायिक निपटारे के लिए जाए तो न्यायालय उसे सुनने से इनकार कर दे। हमारे देश के न्यायालय कानूनी आधार पर ही मामले को स्वीकृत या खारिज करते हैं। अगर इन मामलों को न्यायालय ने स्वीकार किया तो साफ है कि अपीलकर्ताओं ने वैसे तत्व तर्क दिए हैं, जिनसे न्यायालय को लगा कि मामले सुनवाई और फैसले के योग्य हैं। इन मामले को न्यायालय में ले जाने या न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के विरोध में भारत का कोई निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है।

मुसलमानों में वैसे लोग जो मस्जिद समर्थक हैं या इनके आधार पर अपने समुदाय में जिनका महत्त्व बना हुआ है या वे भाजपा संघ विरोधी हैं और स्वयं को सेकुलर लिबरल मानते हैं, वही अलग-अलग तरीके से विरोध में आवाज उठा रहे हैं। देश का बहुमत या यूं कहे बहुसंख्य हिंदू समाज वर्षो से यह मानता रहा है कि उसके प्रमुख धर्मस्थलों को इस्लामी शासकों ने ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई। यह केवल कपोल कथाओं पर आधारित विश्वास नहीं है। जो इसे कपोल कल्पना मानते हैं, उनके लिए भी यही उचित होगा कि एक बार इनका न्यायालयों में निपटारा हो जाने दें। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन लोगों को निराश किया है जो मानते थे कि वाराणसी के सिविल कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने, सर्वे कराने और शिवलिंग के दावे के बाद उसे सील करने का आदेश कानून की दृष्टि से सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि सर्वे कराना और शिवलिंग के दावे के स्थान को सील करना गलत नहीं है। उसने यह भी कहा है कि अगर मामला दो धर्मो के बीच का यानी हाइब्रिड हो तो उसके धार्मिक स्वरूप का निस्तारण करना पड़ता है। यह बात समझ से परे है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा वर्षो से होती आ रही थी तो उसे फिर से शुरू करने की अपील गलत कैसे हो गई? वास्तव में अयोध्या मामले में पहले 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बाद में 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही भारत के मुसलमानों के बीच यह झूठ फैलाया गया कि बिना तथ्य के बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दे दी गई। टीवी चैनलों के डिबेट में आप देख रहे हैं कि कैसे न्यायालय को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ही लिखा कि आस्था और विश्वास के आधार पर टाइटल सूट यानी स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में साफ लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज इतने तथ्यपूर्ण और तार्किक हैं कि उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायालय ने यह अवश्य कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इससे आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। यानी मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दे सका जिससे प्रमाणित हो कि उन्होंने खाली जगह पर मस्जिद निर्माण किया था। इसके ठीक विपरीत हिंदू पक्ष ने ऐसे अनेक प्रमाण दिए जिनसे उनका दावा मजबूत होता है। इस तरह के सारे तथ्यों को नकार कर आज तक दुष्प्रचार यही है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि उसने लोगों की धार्मिक आस्था को महत्त्व दे दिया। ठीक इसी तरह का माहौल इन मामलों में भी बनाने की कोशिश हो रही है।

आखिर दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं तो उपाय यही है कि तत्काल अंदर बाहर सतह की पूरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराकर देख लिया जाए कि सच क्या है। कायदे से तो पूरा सब्रे ही सार्वजनिक होना चाहिए था। जो कुछ है उसे छिपाने की आवश्यकता क्या है? हिंदू पक्ष तो ऐसा नहीं कर रहा। लिखना न्यायालय का आदेश एक बात है, लेकिन अगर मस्जिद का दावा सच है तो फिर सर्वे के सार्वजनिक होने से डर क्यों? अगर सर्वे में शिवलिंगनुमा आकृति दिखी है जो कि लंबे समय से कायम मान्यताओं, कथाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप है तो उसे सुरक्षित करने तथा वजूखाना को सील करने का आदेश ही सर्वाधिक उपयुक्त रास्ता था। सर्वोच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने तथा वजू के लिए अलग व्यवस्था करने की जो बात कही उत्तर प्रदेश प्रशासन उसे क्रियान्वित कर रहा है।

इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भी न्यायालय के विरु द्ध माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि उसने कह दिया है कि 1991 का पूजा स्थल कानून इसमें लागू नहीं होता।

ध्यान रखिए, दोनों मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ले जाए गए और वहां से खारिज हुए। मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करने वाले आम मुसलमानों में भी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पूरे भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले इन चेहरों की सच्चाई कुछ और है। जाहिर है, न्यायालय सहित सभी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले ऐसे तत्वों का प्रभावी और आक्रामक तरीके से विरोध करना होगा ताकि फैलाए जा रहे झूठ और आशंकाओं का पूरी तरह खंडन हो सके।

क्रांतिकारी बदलाव से बदलेगी तस्वीर

प्रमोद भार्गव

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब देश में डिजिटल तरीके से ऑनलाइन जनगणना होगी, जिसके आंकड़े शत-प्रतिशत सही होंगे।

डिजिटल तरीके से की गई जनगणना के आधार पर अगले 25 सालों की नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। ई-बाजार, ई-आवेदन, ई-रेल व बस में आरक्षण, ई-भुगतान के बाद अब ई-जनगणना की भी देश में शुभ शुरुआत होने जा रही है। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे।

यह क्रांतिकारी बदलाव 2024 से प्रत्येक जन्म और मृत्यु की जानकारी ऑनलाइन जनगणना की सुविधा प्राप्त होने के साथ ही आरंभ हो जाएगी। जनगणना-2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी आनलाइन सुविधा दी गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं। जनगणना (संशोधन)-2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारूप भर सकता है। याद रहे यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते संभव नहीं हो पाई। अब इस आनलाइन गणना के साथ आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की गिनती जल्द से जल्द तो होगी ही सटीक भी होगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आनलाइन प्रयोग अद्वितीय हैं, लेकिन देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत जरूरी था कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए। गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तेज भागती यांत्रिक व कंख्यूटरीकृत जिदंगी में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार व संरचना का दस साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता?

वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर मे विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरूरी है कि हम जनगणना की परांपरा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं? जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदाथरे व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के पर्याप्त उपायों के इजाफे के पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। भारत की जनसंख्या 1901 में 23,83,96,327 थी। आजादी के साल 1947 में यह आबादी 34.2 करोड़ हो गई थी। 1947 से 1981 के बीच भारतीय आबादी की दर में ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई और आबादी 68.4 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ 60 लाख आबादी बढ़ जाती हैं। इस दर के अनुसार हमें अपने देश की करीब एक अरब 30 करोड़ लोगों की एक निश्चित जनसंख्या प्रारूप में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों और संसाधनों के समतुल्य आर्थिक व रोजगारमूलक विकास का खाका खींचा जा सके। जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे उसका मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है। हरेक दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब 20 लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी-दल को उसके स्थानीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूर गांव में भेज दिया जाता है। ऐसी हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। इसलिए जरूरी था कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदलकर एक ऐसे स्वरूप में तब्दील किया जाए, जिससे इसकी गिनती में निरंतरता बनी रहे।

इसके लिए न भारी भरकम संस्थागत ढांचे की जरूरत है और न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती की केंद्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेंद्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। देश की सबसे छोटी राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खंड व जिला स्तर तक है। हमें करना सिर्फ इतना है कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रखनी है। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंख्यूटर में फीड जनसंख्या प्रारूप पर भी दर्ज हो। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव ही नहीं है। बहरहाल ई-जनगणना कराने का निर्णय एक दूरदर्शी पहल है।

यूक्रेन संकट में उपेक्षित अफ्रीका

भारत डोगरा

हालांकि इस समय विश्व का अधिकांश ध्यान पूर्वी यूरोप व वहां भी विशेषकर यूक्रेन पर केंद्रित है, पर यदि यह पूछा जाए कि लंबे समय से सबसे अधिक समस्याओं से कौन-सा क्षेत्र जूझ रहा है, तो निश्चय ही यह अफ्रीका महाद्वीप है। पहले कहा जाता था कि उत्तरी अफ्रीका की समस्याएं अपेक्षाकृत कम हैं। मुख्य समस्याएं उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में हैं, यानी उस क्षेत्र में, जो सहारा रेगिस्तान में या उसके दक्षिण में है। अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उप-सहारा क्षेत्र में ही है। आंतरिक हिंसा व अकाल से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित रहा है।

हाल के समय में उत्तरी अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों, जैसे लीबिया व मिस्र की स्थिति में भी बहुत गिरावट आई है व इनकी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध व आंतरिक हिंसा ने अफ्रीका में सर्वाधिक क्षति की है। कांगो, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया, इथियोपिया जैसे कई देश आंतरिक हिंसा के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से अनेक देशों में हिंसा भड़काने में वहां की पूर्व औपनिवेशिक ताकतों ने भी भूमिका निभाई है।

लीबिया कभी अपनी तेल संपदा के कारण बहुत समृद्ध था, जिसका लाभ पड़ोस के चाड व माली जैसे निर्धन देशों को भी मिल जाता था। पर लीबिया में गृहयुद्ध भड़कने के बाद इन पड़ोसी देशों में भी निर्धनता व भूख की समस्या बहुत बढ़ गई है। पैट्रिस लुमुम्बा जैसे अति लोकप्रिय नेता यदि अफ्रीका में भूख व गरीबी दूर करने का सपना साकार नहीं कर सके, तो इसका जिम्मेदार पश्चिमी देश व पूर्व औपनिवेशिक ताकतें रही हैं। एक समय था, जब मिस्र, सूडान व मोरक्को जैसे अफ्रीकी देश समृद्ध थे।

अफ्रीका में मुख्य समस्याएं तब शुरू हुईं, जब बाहर से आए आक्रामक गोरे व्यापारियों ने कुछ स्थानीय स्वार्थी तत्वों की सहायता से पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के आसपास गुलाम व्यापार आरंभ किया। इसमें बहुत हिंसा हुई व जिन अफ्रीकियों का अमेरिकी महाद्वीप में गुलामी के लिए अपहरण किया गया, उनमें से लाखों की मौत हो गई। इसके बाद औपनिवेशिक ताकतों की क्रूर हिंसा का क्रम आरंभ हो गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में यह अपने चरम पर पहुंचा, जब विभिन्न पश्चिमी ताकतों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया।

औपनिवेशिक ताकतों की एक नजर जहां अफ्रीका के मूल्यवान खनिजों पर थी, वहीं दूसरी नजर अपनी जरूरत के खाद्यों व कच्चे माल के उत्पादन के लिए वहां की धरती के उपयोग पर भी थी। उन्होंने अफ्रीकी संसाधनों का दोहन इस तरह से किया कि उसकी समृद्धि के आधार में जो परंपराओं का ताना-बाना था, वह टूटने लगा। वहां के परंपरागत ज्ञान में इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि स्थानीय हित के लिहाज से संसाधनों का कम दोहन हो। जहां उपजाऊ भूमि व जल संसाधन अधिक थे, वहां नियमित खेती होती थी और विविध खाद्यों व फसलों को उगाने पर जोर दिया जाता था।

वहां घुमंतू पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ताकि एक स्थान पर संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो। उनके मार्ग तय थे व उनका किसानों के साथ आपसी सहयोग एवं तालमेल था। पर औपनिवेशिक शासकों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस अपने स्वार्थ से मतलब था। नतीजतन अनुचित नीतियों के चलते अफ्रीका की परंपरागत व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न होने लगीं व अकाल तथा भूख का ऐसा दौर आरंभ हुआ, जो आज तक नहीं थमा है।

पश्चिमी देश आज भी खनिजों की लूट पर अधिक ध्यान देते हैं व जिन क्षेत्रों में इनका भरपूर दोहन हो चुका है, उसे उपेक्षित छोड़ देते हैं।

बेशक वहां संयुक्त राष्ट्र व उसके खाद्य विकास कार्यक्रम की तरफ से खाद्य वितरण कार्यक्रम चल रहे हैं, पर इनसे अल्पकालीन राहत ही मिल सकती है। अफ्रीका को टिकाऊ व व्यापक विकास कार्यक्रम चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि अफ्रीकी लोगों के हितों के अनुकूल नीतियां बनें और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय मिले। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अफ्रीकी निर्यातों को उचित मूल्य मिले। पूरे अफ्रीका महाद्वीप को हाशिये पर रखने की प्रवृत्ति खतरनाक है।

झारखंड से राज्यसभा जा सकते हैं कपिल सिब्बल

रांची, 24 मई (एजेन्सी)। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए आगामी 15 जून को होनेवाले चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गयी, लेकिन इसे लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष में से किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के रूप में मशहूर अधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का नाम सबसे तेजी से उछला है। इसके अलावा सुबोधकांत सहाय, अविनाश कुमार पांडेय, डॉ अजय कुमारके नाम की भी चर्चा है। 82 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में संख्याबल का जो गणित है, उसके हिसाब से 48 सदस्यों वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह किइस सुनिश्चित सीट पर कपिल सिब्बल का नाम कांग्रेस ने आगे नहीं किया है, बल्कि यह चर्चा झामुमो के खेमे से उठ रही है। झारखंड में माइनिंग लीज के आवंटन से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक पीआईएल पर चल रही सुनवाई में कपिल सिब्बल बतौर अधिवक्ता उनकी पैरवी कर रहे हैं।

कानूनी उलझनों वाले दो अन्य मामलों में भी सिब्बल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के पैरवीकार हैं। सत्ता के अंत:पुर से जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके मुताबिक सरकार सिब्बल को उनकी कानूनी सेवाओं के एवज में राज्यसभा में भेजना चाहती है। बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन में झामुमो के विधायकों की संख्या 30 है, जबकि कांग्रेस के पास 16 और राजद के पास एक विधायक है। दो साल पहले हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने झामुमो के प्रत्याशी शिबू सोरेन के पक्ष में मतदान किया था, लिहाजा कांग्रेस का दावा है कि इस बार राज्यसभा की सीट पर उसकी दावेदारी बनती है। इसे लेकर झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी।

अब इस मसले पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के साथ 25 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को सीट देने पर सहमत हैं, लेकिन इसके लिए वह अपनी ओर से कपिल सिब्बल का नाम कांग्रेस आलाकमान के पास रखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई और तमाम स्थानीय नेता कपिल सिब्बल के नाम पर शायद ही सहमत हों। कांग्रेस आलाकमान के दरबार में झारखंड के जिन नेताओं की दावेदारी प्रमुखता से पहुंची है, उनमें पूर्व केंद्रीय सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय, पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक उम्मीदवार के नाम पर आखिरी मुहर पार्टी आलाकमान की ओर से लगेगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस या झामुमो की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले एक हफ्ते के अंदर उम्मीदवारी की तस्वीर साफ हो सकती है।

झारखंड से राज्यसभा की दूसरी सीट पर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा की दावेदारी मजबूत है, लेकिन अगर इस सीट के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन नेभी प्रत्याशी उतार दिया तो बीजेपी का प्रत्याशी कठिन संघर्ष में उलझ सकता है। इस सीट के लिए भाजपा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, महेश पोद्दार, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका के नाम भी चर्चा में हैं।

हर परिस्थिति में खुद को रखें कॉन्फिडेंट

नौकरी के दौरान अक्सर एक जैसा काम करते हुए हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें जरा-सा बदलाव भी हमें असहज कर देता है। लगातार सुविधापूर्ण स्थिति में आत्ममुग्ध रहना एक तरह से 'असुविधा'' को ही दावत देना है। अगर आप भी कंफर्ट जोन में खुद को 'कंफर्टेबल' मानकर चल रहे हैं, तो वक्त रहते संभल जाएं और ऐसा करके ही आप खुद को हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंट रख सकेंगे।

सदाशिव पढ़ाई में अच्छे हैं। दिखने में समझदार। नौकरी जल्द शुरू कर दी थी। कुछ ही साल में अपनी पहचान भी बना ली और एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए अलग से काम करके उनका विश्वास भी हासिल कर लिया। इसका उन्हें फायदा भी मिलता रहा। पद और प्रतिष्ठा तो मिली ही, कई बार विदेश जाने का अवसर भी मिला। मगर कई साल ऐसे ही बीतने के कारण सदाशिव आत्ममुग्धता के शिकार होते चले गए। प्रभावशाली अधिकारी का संरक्षण मिला होने के कारण वे खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करने लगे। इस बीच उन्हें कई प्रोजेक्ट मिले, पर भरपूर अवसर मिलने के बावजूद किसी में खास प्रभाव छोड़ न पाने के कारण अंतत: वे अपने मूल विभाग में ही बने रहे। यहीं उनसे चूक होती चली गई। अपने मूल विभाग के बॉस से उनकी ट्यूनिंग बनने और प्रगाढ़ होने के बजाय बिगड़ती चली गई लेकिन आत्ममुग्धता और उच्चाधिकारी की शह के कारण उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। विभागीय बॉस के उपेक्षापूर्ण नजरिये से ठेस लगने के बावजूद उनका स्वाभिमान नहीं जागा और वे निश्चिंतता के साथ टाइम पास करते रहे। इतना ही नहीं, सोशल साइट्स पर भी वे खूब दिखते और अपनी बेतुकी टिप्पणियों पर खुद ही खुश हो लेते। कुछ समय बाद स्थितियां करवट लेने लगीं। प्रभावशाली अधिकारी का प्रभाव जाता रहा और एक समय ऐसा भी आया, जब उनकी जगह कंपनी में कोई और आ गया। अब सदाशिव को सचेत हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका रवैया जस का तस बना रहा। वे चाहते, तो अपने विश्वासी अधिकारी के रहते किसी और विभाग या केंद्र या प्रोजेक्ट में अच्छे पद पर शिफ्ट हो सकते थे लेकिन सुविधाजीवी और एकरस जीवन के आदी हो चुके सदाशिव ने ऐसी कोई पहल नहीं की। एक दिन जब उन्हें कुछ गलतियां बताते हुए संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तब उन्हें एहसास हुआ लेकिन तब उनके पास संभलने और सुधरने का मौका नहीं था।

भंवर है कंफर्ट जोन

सदाशिव की सच्ची कहानी महज एक उदाहरण है। आपको अपने संस्थान या दूसरी संस्थाओं, विभागों में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो कंफर्ट जोन में समय बिताते हुए खुश दिखेंगे। कई लोग यह भी कहते मिल जाएंगे कि अरे भाई, नौकरी तो सुरक्षित है ही, फिर काम की टेंशन में क्यों परेशान रहें! दरअसल, ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि इस प्रकार का रवैया रखकर वे खुद के नुकसान की ही नींव रख रहे हैं। स्थितियां हमेशा एक-सी नहीं रहतीं। जो लोग काम से जी चुराते हैं, नया सीखने-जानने में दिलचस्पी नहीं रखते, कभी पहल करके कोई काम नहीं करते, कोई काम कहने पर समाधान के बजाय तमाम तरह की समस्याएं ही गिनाने बैठ जाते हैं, टीम मेंबर्स से भी जिन्हें ढेरों शिकायतें होती हैं, सही मायने में उनका करियर हमेशा दांव पर लगा होता है। ऐसे लोगों को जब कभी कोई काम सौंपा जाता है, तो वे उसमें इतना विलंब कर देते हैं या फिर उसे इतना उलझा देते हैं कि बॉस को आगे उन्हें काम न देने के बारे में सोचना पड़ जाता है। ऐसे लोग अपनी इस कथित रणनीति पर भले ही खुश होते हों पर जरा सोचें, क्या वह बॉस कभी उनकी प्रशंसा-अनुशंसा करेगा और जब कभी डिमोशन न कर दिया गया या इंक्रिमेंट रोक लिया गया या फिर छंटनी की स्थिति में उनका नाम ही आगे बढ़ा दिया गया, तो फिर क्या उन्हें संस्थान और बॉस की आलोचना का अधिकार होना चाहिए

उपयोगिता करें साबित

आप निजी कंपनी में काम कर रहे हों या फिर सरकारी सेवा में हों, छोटे पद पर हों या बड़े पद पर, अगर आप अपने पद की जरूरतों के अनुसार खुद की उपयोगिता साबित करने का प्रयास नहीं करते, तो एक-न-एक दिन आपको जरूर नुकसान हो सकता है। अगर आप समय रहते नहीं चेतते, तो फिर आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते। आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि उसमें बॉस से और समझने की या किसी सहयोगी की मदद लेने की जरूरत है, तो विनम्रता के साथ सहयोग लें। आपके प्रयास की गंभीरता स्पष्ट नजर आनी चाहिए। अगर आप छोटे-से-छोटे काम को भी सतर्कता के साथ बहुत अच्छी तरह पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपकी छवि बेहतर होगी।

हर दिन हो नया

अगर आप एकरस जीवन से बचना और खुश रहना चाहते हैं, तो अपने काम को एंजॉय करना होगा। निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे, तो ज्यादा कुछ मिले-न मिले, भरपूर सुकून जरूर मिलेगा। यह आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसके अलावा गलतियों से सबक लेने, कमियों को दूर करने और हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रखेंगे, तो आपके आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा और आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी उत्साह और हौसले से कर सकेंगे। इस राह पर चलकर तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ते जाएंगे।

ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में जॉब

हाल ही में ग्रेजुएशन करने वालों के लिए अमेरिका में काम करने के लिए दो ऑप्शन हैं : ऑप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) तथा एच1बी वीसा। ओपीटी ऐसे ताजा ग्रेजुएट्स के लिए एक कार्यक्रम है, जो अपनी पढ़ाई की फील्ड में कार्य अनुभव पाना चाहते हैं। इसके लिए दो शर्तें पूरी करना जरूरी है : पहली यह कि आपकी ओपीटी जॉब का सीधा संबंध आपकी डिग्री से होना चाहिए। मसलन, यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में डिग्री ली है, तो आप शेफ के रूप में नौकरी नहीं कर सकते। दूसरी शर्त यह है कि आपने जहां से डिग्री प्राप्त की है, वहां का कोई अधिकारी ओपीटी प्रोग्राम के लिए आपका नाम प्रस्तावित करे। इसलिए यह जरूरी है कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, उस संस्थान के संपर्क में रहें और उससे अच्छे संबंध रखें। आम तौर पर ओपीटी 1 साल के लिए ही होता है। मगर यदि आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या गणित में डिग्री ली है, तो आप ओपीटी को अतिरिक्त 17 महीनों के लिए बढ़वा सकते हैं। एच1बी वीसा ऐसे लोगों के लिए है, जो किसी स्पेशिएलिटी ऑक्युपेशन में काम करते हैं। यह एक पिटिशन-बेस्ड वीसा है, यानी आपकी ओर से आपकी कंपनी इसके लिए यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के समक्ष आवेदन करेगी। एच1बी वीसा प्राप्त करने के लिए आपको किसी यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। एच1बी वीसा पर आप अमेरिका में 3 साल तक काम कर सकते हैं। इसकी अवधि बढ़वाने के विकल्प भी हैं मगर कुल मिलाकर आप एच1बी वीसा पर अमेरिका में अधिकतम 6 वर्ष तक ही काम कर सकते हैं।

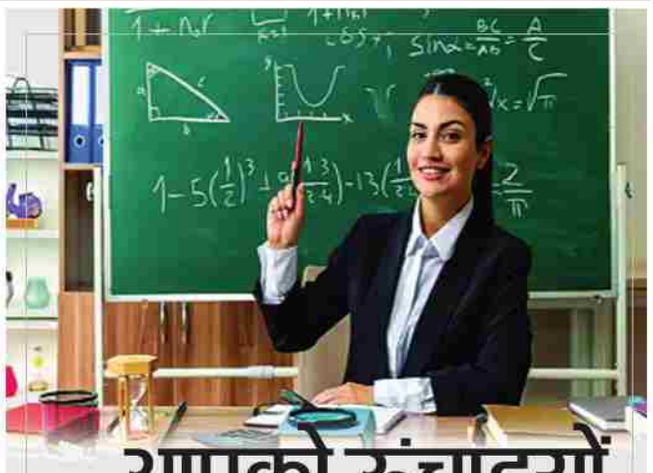

आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे ये करियर ऑप्शन

आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणित में 8 ऐसे करियर ऑप्शन जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

छात्रों के बीच गणित विषय को कठिन विषय समझा जाता है, इसका नाम सुनते ही बहुत से छात्र दूर भागते हैं। परंतु यदि प्रारंभ से ही गणित विषय को सही प्रकार से हैंडिल किया जाए तो आपकी गणित पर अच्छी पकड़ हो सकती है। गणित विषय का अर्थ केवल जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देना नहीं है। इस विषय में उच्च शिक्षा लेकर करियर की अपार संभावनाएं हैं। गणित विषय मनुष्य की ज्ञान की एक उपयोगी तथा आकर्षक शाखा है। इसमें अध्ययन के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत में प्राचीन काल से ही गणित की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। प्राचीन काल के कई गणितज्ञों आर्यभट्ट, वराह मिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य इत्यादि ने तथा आधुनिक काल में डॉ गणेश प्रसाद, प्रोफेसर बीएन प्रसाद, श्रीनिवास रामानुजन इत्यादि ने गणित की सुदृढ़ नींव रखी है।

इकोनॉमिस्ट

एक इकोनॉमिस्ट आर्थिक रुझानों का अन्वेषण करके मूल्यांकन करता है। भविष्य को लेकर पूर्वानुमान जारी करता है। वह विभिन्न विषयों जैसे महंगाई, कर, ब्याज दर, रोजगार का स्तर आदि का डेटा संग्रह करता है। उस पर अनुसंधान करता है और विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्री बनने के लिए गणित विषय को जरूरी माना जाता है। एक अर्थशास्त्री बनने के लिए अर्थशास्त्र में बैचलर डिग्री होना और गणित पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। इसके बाद अर्थशास्त्र, इकोमेट्रिक्स, ऐप्लाइड इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेर इंजीनियरिंग के छात्रों के करियर की नीव शुरू ही गणित के ज्ञान से होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का काम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और उसे डेवलप करना होता है। इस काम में छात्रों को कम्प्यूटर साइंस के साथ-साथ मैथ्स की थ्योरी और उनके सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र में एक्सपर्ट छात्रों के लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद है तथा अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं आने वाली हैं जो छात्रों के हित में मददगार साबित होंगे।

स्टैटिस्टिक्स

गणित पर जिनको महारत हासिल है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स में कैरियर बनाना बहुत अच्छा विकल्प है। सांख्यिकीविद को डाटा का विश्लेषण करना, परिणामों को पाइ चार्ट्स, बार ग्राफ, टेबल के रूप में प्रस्तुत करने का काम करना होता है। हेल्थ केयर, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सांख्यिकीविद की काफी मांग होती है। सांख्यिकीविद बनने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में स्नातक की डिग्री या फिर स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए।

चार्टर्ड एकाउंटेंट

चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने का पहला रूल ही गणित में दक्ष होना है। क्योंकि चार्टर्ड एकाउंटेंट यानि कि सीए का पूरा काम एकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि के चलते फाइनेंस और एकाउंट से जुड़े क्षेत्रों में करियर के काफी स्कोप जुड़ते जा रहे हैं जो गणित में रूचि रखने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प का मार्ग है।

ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट

इससे जुड़े काम को एप्लाइड मैथ्स और फॉर्मल साइंस की एक शाखा के रूप में ही समझा जाता है। इसमें आधुनिक लॉजिकल विधियों जैसे की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट इन्हीं आधुनिक विधियों कि मदद से मैनेजर को सही निर्णय लेने और समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव प्रदान करते है।

बैंकिंग

अगर आपकी गणित में अच्छी पकड़ है तो आप बैंकिंग क्षेत्र में आप एकाउंटेंट, कस्टमर सर्विस, फ्रंट डेस्क, कैश हैंडलिंग, एकाउंट ओपनिंग, करंट एकाउंट, सेविंग एकाउंट, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिकवरी ऑफिसर के प्रोफाइल्स के लिए भी कोशिश कर अपना भविष्य बना सकते है क्यूंकि इन सभी में मैथमेटिकल स्किल्स का होना जरूरी है।

मैथमेटिशियन

अगर आप मैथ को दिल से प्यार करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा माहिर हैं, तो मैथमेटिशियन बनना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यह ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैथ्स के बुनियादी क्षेत्र का अध्ययन या रिसर्च संबंधी कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लॉजिक, ट्रांसफार्मेशन, नंबर आदि समस्याओं का निर्धारण करते हैं। इस क्षेत्र में भी मैथ्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है तथा इस क्षेत्र में छात्र अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट

कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट आईटी टूल्स का उपयोग करते हुए किसी भी एंटरप्राइजेज को लक्ष्य पूरा करने में मदद पहुंचाते हैं। यदि आपको गणित का ज्ञान नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते और इसी के विपरीत यदि आपका गणित के प्रति रुझान है तो आप आसानी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ज्यादातर सिस्टम एनालिस्ट अपना काम कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं तथा इसे ठीक तरह से समझने के लिए गणित पहली नींव है।

उत्साह और जुनून के साथ देशभक्ति

वायु सेना में करियर

भारतीय वायु सेना में करियर बनाने के लिए ऊर्जावान, उत्साही युवाओं की हमेशा मांग रहती है। क्या आप इस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। एयर फोर्स, यानी वायु सेना में करियर को प्रतिष्ठित माना जाता है और युवाओं में यह खासा लोकप्रिय भी है। इस फील्ड में यदि आप करियर बनाते हैं, तो आपका नाता देश सेवा, नवीनतम टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट शारीरिक मानसिक कौशल से होगा।

भारतीय वायु सेना को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जो ऊर्जावान हों, पैशनेट हों, उत्साही हों और जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। मगर ध्यान रहे, एयर फोर्स का हिस्सा होने में खासे परिश्रम की जरूरत होती है। इसकी चयन प्रक्रिया बहुत कड़ी है। इसमें प्रेक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिजिकल तथा मेडिकल टेस्ट, सायकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क आदि शामिल होते हैं।

कैसे हों शामिल

भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए आपको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। यदि आपकी उम्र साढ़े 16 साल से 19 साल है, आप भारतीय नागरिक हैं और आपने फिजिक्स तथा मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास की है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। चयन के बाद उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 साल की गहन ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी समाप्ति पर एयर फोर्स अकादमी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। ग्रेजुएट भी एयर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आरंभिक चयन के बाद शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एयर फोर्स ट्रेनिंग संस्थान में भेजा जाता है।

कौन-कौन सी ब्रांच

एयर फोर्स में करियर के अवसरों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है : फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच तथा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच।

फ्लाइंग ब्रांच

इस ब्रांच में विभिन्न श्रेणियों के पायलटों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस ब्रांच में आकर आपको उड़ान भरने के भरपूर मौके मिलेंगे। इसमें हैलिकॉप्टर पायलट, फाइटर पायलट तथा ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में ग्रेजुएट्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अनेक अवसर हैं। पायलट ट्रेनिंग हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर डंडीगल स्थित एयर फोर्स एकेडमी में दी जाती है। इस ब्रांच में शामिल होने के बाद आपको आपके डेजिग्जनेशन, ट्रेनिंग व अनुभव के आधार पर विभिन्न मिशनों का हिस्सा बनाया जाएगा।

टेक्निकल ब्रांच

एयर फोर्स की टेक्निकल ब्रांच अत्याधुनिक विमानों तथा शस्त्रों के सही संचालन को सुनिश्चित करती है। यह विमानों के मेंटेनेंस तथा सर्विसिंग और एयर फोर्स स्टेशन पर कम्युनिकेशन तथा सिग्नल से संबंधित कार्यों को करने के लिए क्रमश : मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों से एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स को नियुक्त करती है।

ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच

यह ब्रांच मानव तथा अन्य संसाधनों का प्रबंधन कर वायु सेना का संचालन करती है। दरअसल यह एक ब्रांच न होकर इसमें अनेक ब्रांच समाहित हैं, जैसे : एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, जिसके अधिकारी समस्त संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। इसके कुछ अधिकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर व फ्लाइट कंट्रोलर के रूप में भी काम करते हैं। इसी प्रकार अकाउंट्स ब्रांच में अकाउंट्स संबंधी तमाम काम किए जाते हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच के अधिकारियों को कपड़ों से लेकर विमानों के पुर्जों तक तमाम तरह के सामान का प्रबंधन करना होता है। एजुकेशन ब्रांच के अधिकारी भविष्य के वायु सैनिकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करते हैं। मीटियॉरोलॉजी ब्रांच के अधिकारी उड़ान भर रहे पायलटों को गाइड कर उनकी उड़ान सुरक्षित करने में मदद करते हैं।

जून में और महंगा होगा कर्ज

महंगाई से चिंतित आरबीआई, गवर्नर ने दिए रेपो रेट में बढ़ोतरी के संकेत

मुंबई। केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ी चिंता है। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई जून में एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। इस बात के साफ संकेत आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने दिए हैं। इससे कर्ज और महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए मई के पहले हफ्ते में भारतीय रिजर्व बैंक ने आनन-फानन में एमपीसी की बैठक बुलाकर रेपो दरों में 0.40 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिससे होम और ऑटो समेत लगभग सभी तरह के कर्ज महंगे हो गए थे। लेकिन महंगे कर्ज से फिलहाल जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप की ईएमआई में जून से और बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह बैंकों से कर्ज लेना और महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के ऐलान के बाद अब आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया आगे होने वाली बैठक में रेपो दरों में और बढ़ोतरी की जा सकी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महीने

की शुरुआत में नीतिगत दरों को बढ़ाकर 4ण्0 किया गया था। अब इन्हें 5.15 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि कोरोना पूर्व का स्तर था। गौरतलब है कि आरबीआई मौद्रिक समिति एमपीसीद्धकी अगली बैठक जून में होने वाली है, जिसमें रेपो दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिए जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमिक रिकवरी जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के लिए वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ी चिंता है।

लिमिट से पार महंगाई

मई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79 फीसदी हो गई थी। खाने-पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई आठ साल के पीक पर पहुंच गई। मई 2014 में महंगाई 8.32 फीसदी थी। यह लगातार चौथा महीना था,जब महंगाई दर आरबीआई की छह फीसदी की ऊपरी लिमिट के पार रही थी। फरवरी में यह 6.07 फीसदी, जनवरी में 6.01 थी।

रुपए की गिरावट रोकेगा आरबीआई

लगातार कमजोर हो रहे रुपए को लेकर आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि सेंट्रल बैंक करेंसी मार्केट में रुपए की अत्यधिक अस्थिरता को रोकेगा। चालू खाते घाटे को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वह इसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहाए, भारत का निर्यात मजबूत बना हुआ है। तरलता के अनुमान पर गवर्नर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक मल्टी-ईयर टाइम साइकिल में इकोनॉमी में लिक्विडिटी की स्थिति को सामान्य करने पर विचार कर रहा है।

दुनियाभर में बढ़ी है महंगाई

दास ने दुनिया भर में क्या हो रहा है इसका एक उदाहरण देकर स्थिति को समझाया। दास ने कहा, रूस और ब्राजील को छोड़कर लगभग हर देश में ब्याज दरें नकारात्मक हैं। एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए महंगाई का लक्ष्य लगभग 2 फीसदी है। जापान और एक अन्य देश को छोड़कर सभी एडवांस्ड इकोनॉमीज में महंगाई सात फीसदी से ज्यादा है। ब्याज दरों के निगेटिव होने का मतलब है कि सवाधि जमा पर आपको महंगाई की दर से कम ब्याज मिलना है। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग मीटिंग 6-8 अप्रैल को हुई थी। अगली मीटिंग जून में होगी।

4जी ग्राहकों के लिए जियो का धमाका ऑफर

जियोफोन नेक्स्ट पर 2000 रुपए की छूट

मुंबई। अगर आपके घर पर कोई भी पुराना 4जी फोन रखा है तो आप आसानी से जियोफोन नेक्स्ट पर 2000 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। रिलायंस रिटेल ने लिमिटेड समय के लिए जियोफोन नेक्स्ट एक्सचेंज टू अपग्रेड ऑफर लॉन्च किया है। जियोफोन नेक्स्ट की कीमत 6499 रुपए है जोकि डिस्काउंट के बाद 4499 रुपए हो जाएगी। रिलायंस जियो और गूगल ने साथ में रिसर्च कर किफायती स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट बनाया है। ऑफर के तहत किसी भी कंपनी का 4जी फीचर फोन या स्मार्टफोन दिया जा सकता है। ग्राहक पुराना थ्रियोफोन भी देकर भी 2000 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको अपने नजदीक के जियोमार्ट और रिलायंस डिजिटल स्टोर्स पर जाकर 4जी फोन देना है। जियोफोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग के समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा था कि वहन भारतीय जो अंग्रेजी में सामग्री को पढ़ने में सक्षम नहीं हैए वे इस स्मार्ट डिवाइस पर अपनी भाषा में इसका अनुवाद और यहां तक कि पढ़ भी सकते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाट रहे हैं।

स्मार्टफोन में बेहतरीन फीचर्स

इस स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स हैं। इसके कैमरा में ही ट्रांसलेशन फीचर है। ट्रांसलेशन फीचर के जरिए किसी भी भाषा के टेक्स्ट का फोटो खींचकर उसका ट्रांसलेशन अपनी भाषा में कर सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। जियोफोन नेक्स्ट में हाथ से टाइपिंग का झंझट नहीं है। आप लाइव ट्रांसक्राईब एप का उपयोग कर आप आसानी से अपनी भाषा में टाइप कर सकते हैं। आप इसमें ओटीजी सपोर्ट वाली पेनड्राइव भी लगाकर उपयोग कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन 5.45 इंच एचडी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, जियो और गूगल के प्रीलोडेड एप्स, प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल सिम, ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेटए एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग, 13 मेगापिक्सल रियर कैमराए,8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, बैटरी 3500 एमएएच जैसी अन्य खूबिया हैं।

रिलायंस-बीपी का सरकार को पत्र

ईंधन का खुदरा कारोबार घाटे का सौदा

हर माह 700 करोड़ रुपए का नुकसान

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के संयुक्त उद्यम आरबीएमएल ने सरकार से कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र के लिए ईंधन का खुदरा कारोबार अब आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है। आरबीएमएल का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ईंधन बाजार पर नियंत्रण है और वे पेट्रोल और डीजल का दाम लागत से नीचे ले आती हैं। इससे निजी क्षेत्र के लिए इस कारोबार में टिके रहना संभव नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पहले नवंबर, 2021 से रिकॉर्ड 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम को बरकरार रखा। उस समय उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। पिछले महीने से फिर पेट्रोल, डीजल कीमतों में वृद्धि को रोक दिया गया है। यह सिलसिला अब आरबीएमएल अपने खुदरा परिचालन में कटौती कर रही है जिससे हर महीने होने वाले नुकसान में कुछ कमी लाई जा सके। कंपनी को पेट्रोल और डीजल की लागत से कम मूल्य पर बिक्री से हर महीने 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में पेट्रोल और डीजल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे वह अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर सके।

47 दिन से जारी है। एक उच्चपदस्थ सूत्र ने कहा, उन्होंने रिलायंस बीपी मोबिलिटी ईंधन मूल्य के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है। एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि मंत्रालय जल्द आरबीएमएल के पत्र का जवाब देगा। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप दाम नहीं बढ़ाए हैं।

फर्जी आईटीसी दावों पर कसेगी नकेल

नई दिल्ली। सरकार फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के दावों को रोकने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। फर्जी आईटीसी दावों पर नकेल कसने और सही मामलों के तेज निपटान के लिए मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में बदलाव की तैयारी है। एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी परिषद की अगली महीने होने वाली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। जीएसटीआर-3बी एक संक्षिप्त ब्योरा और मासिक जीएसटी भुगतान से संबंधित फॉर्म है। विभिन्न श्रेणी के करदाता हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख को यह फॉर्म भरते हैं। संशोधित फॉर्म करदाता को सकल आईटीसीए किसी विशेष महीने में दावा की गई राशि और करदाता के बही-खाते में शेष बची रकम के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा। अधिकारी ने बताया कि संशोधित फॉर्म की मदद से फर्जी आईटीसी दावों पर न सिर्फ अंकुश लगेगी बल्कि ईमानदार करदाताओं को तेजी से आईटीसी का लाभ मिल सकेगा।

घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतें घटेंगी

15 प्रतिशत तक घट सकते हैं दाम : ईईपीसी

नई दिल्ली। सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल में उत्पाद शुल्क घटाने से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने और इस्पात उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल और फेरो-निकेल सहित कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने से देशभर में इस्पात उत्पादों के दाम 10 से 15 फीसदी सस्ते होंगे।

यह बात इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद ईईपीसीद्ध ने सोमवार को कही। उल्लेखनीय है इस्पात उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार ने शुल्क के मोर्चे पर कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने बीते शनिवार को इस्पात उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल और फेरो-निकेल सहित कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। कुछ इस्पात वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने के सरकार के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईईपीसी इंडिया के

चेयरमैन महेश देसाई ने कहा कि इंजीनियरिंग सामान विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस कदम से लाभ होगा और वैश्विक बाजारों में वें अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। वहीं रियल एस्टेट कंपनियों के निकाय क्रेडाई और नारेडको ने भी इस्पात और सीमेंट की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार के कदमों की सराहना की है। उद्योग निकायों ने उम्मीद जताई है कि विनिर्माता इसका लाभ अपने ग्राहकों को भी देंगे। क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा कि इस्पात उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के कदमों की सराहना की है। उद्योग निकायों ने उम्मीद जताई है कि विनिर्माता इसका लाभ अपने ग्राहकों को भी देंगे। क्रेडाई और नारेडको दोनों पिछले एक साल से इस्पात और सीमेंट की कीमतों में आई तेजी का मुद्दा उठाते रहे हैं। उत्पादों की उच्च कीमतों से समग्र निर्माण लागत में वृद्धि हुई है।

घरेलू इस्पात उद्योग को ऑर्डर पूरे करने के लिए तीन महीने का समय मिले

उद्योग संगठन फिक्की ने सरकार से अनुरोध किया है कि घरेलू इस्पात उद्योग को अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी जाए। फिक्की की इस्पात समिति में सह अध्यक्ष वीआर शर्मा ने कहा, मेरा सुझाव है कि कम से कम तीन महीने का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि जो ऑर्डर लिए जा चुके हैं उनकी आपूर्ति की जा सके। करीब 20 लाख टन इस्पात के ऑर्डर लिए जा चुके हैं जिनके लिए ऋण अनुरोध या बिक्री अनुबंध किए जा चुके हैं। अब कर लगाने से इन ऑर्डर की मौजूदा दरों पर आपूर्ति प्रभावित होगी।

सरकार के कदम से परियोजना लागत घटेगी

रियल एस्टेट कंपनियों को उम्मीद

नई दिल्ली। जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई और नारेडको ने इस्पात और सीमेंट की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार के कदमों की सराहना की है। उद्योग निकायों ने उम्मीद जताई है कि विनिर्माता इसका लाभ अपने ग्राहकों को भी देंगे। क्रेडाई और नारेडको दोनों पिछले एक साल से इस्पात और सीमेंट की कीमतों में आई तेजी का मुद्दा उठाते रहे हैं। उत्पादों की उच्च कीमतों से निर्माण लागत में वृद्धि हुई है। वहीं कई बिल्डरों ने निर्माण लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए घरों के दाम बढ़ा दिए हैं। क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, कच्चे माल की बढ़ती लागत को काबू में लाने के लिये सरकार का कदम सराहनीय है। इस्पात उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के कदम से सभी संबंधित पक्षों को राहत मिलनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शनिवार को सरकार ने इस्पात उद्योग में उपयोग होने वाले कोकिंग कोल और फेरोनिकल समेत कुछ कच्चे माल के आयात पर लगने वाले शुल्क से राहत दी। इससे घरेलू उद्योग की लागत कम होगी और कीमतें कम होंगी। लौह अयस्क के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक और कुछ स्टील मध्यवर्ती वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया।

कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी

पटोदिया ने कहा, लौह अयस्क और स्टील मध्यवर्ती सामान के आयात शुल्क में कमी से घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी, इस्पात उत्पादों के दाम कम होंगे और परियोजनाओं की लागत को काबू में लाने में मदद मिलेगी। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया ने कहा, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र मौजूदा समय में कच्चे माल की ऊंची लागत से जूझ रहा है। ऐसे में ईंधन पर उत्पाद शुल्क को कम करने के बाद लौह अयस्क और स्टील पर शुल्क कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के लौह अयस्क और इस्पात पर निर्यात शुल्क लगाने और इसके आयात शुल्क में कमी के साथ-साथ सीमेंट की आपूर्ति बढ़ाने के कदम से रियल एस्टेट कंपनियां कीमतों को नीचे लाने में सक्षम होंगे।

लंबे समय तक उच्च तापमान भारत के लिए नुकसानदायक

महंगाई बढ़ेगी, वृद्धि भी प्रभावित होगी: मूडीज

नई दिल्ली। भारत जैसे देश के लिए लंबे समय तक उच्च तापमान नुकसानदायक है। इससे देश में एक तरफ तो महंगाई बढ़ेगी वहीं दूसरी तरह आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित होगी। यह बात मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कही। मूडीज के मुताबिक दीर्घावधि में, भौतिक जलवायु जोखिमों के प्रति भारत के अत्यधिक नकारात्मक ऋण जोखिम का मतलब है कि इसकी आर्थिक बढ़त का अस्थिर होना। भारत को लगातार जलवायु संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी के अंत में रूस और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

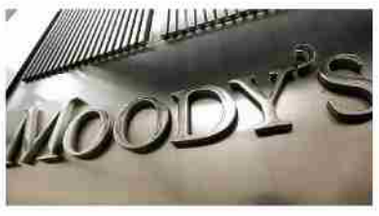

एजेंसी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण भारत के निर्यात भागीदारों को गेहूं की कीमतों में और उछाल का सामना करना पड़ सकता है। मूडीज ने कहा, यह प्रतिबंध ऐसे समय में आया है, जब रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बाद भारत गेहूं की मांग के वैश्विक अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। मूडीज ने कहा कि प्रतिबंध से हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन इससे निर्यात और बाद में वृद्धि को नुकसान होगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वैसे तो भारत में गर्मी की लहर काफी आम हैं, लेकिन यह आमतौर पर मई और जून में अधिक होती हैं। हालांकि, इस साल नयी दिल्ली में मई में गर्मी की पांचवीं लहर देखी गई, जिससे अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया।

गेहूं उत्पादन पर पड़ेगा असर

मूडीज ने कहा, लंबे समय तक उच्च तापमान देश के उत्तर-पश्चिम के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करेगा, जिससे गेहूं उत्पादन पर असर पड़ सकता है। साथ ही यह बिजली की कटौती का कारण भी बन सकता है। इस कारण उच्च मुद्रास्फीति और वृद्धि के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार ने अत्यधिक गर्मी के चलते जून, 2022 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन के अपने अनुमान को 5.4 प्रतिशत घटाकर 15 करोड़ टन कर दिया है साथ ही महंगाई पर काबू करने गेहूं निर्यात रोकने का फैसला लेना पड़ा।

सेल ने स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किया विशेष लोगो

नई दिल्ली। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को यादगार बनाने के लिए सोमवार को एक स्मारक लोगो जारी किया है। सेल ने एक बयान में कहा कि कंपनी वर्ष 2022 में अपनी स्थापना के पचासवें साल का उत्सव मना रही है। लोगो जारी होने के बाद देश भर में स्थित कंपनी के संयंत्रो और इकाईयों में पूरे साल अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेल की स्थापना 24 जनवरी, 1973 में हुई थी। सेल की अध्यक्ष सोमा मण्डल ने कंपनी के निदेशकों की मौजूदगी में लोगो जारी किया जिसमें कंपनी के मूल लोगो को बरकरार रखने के साथ पचास साल के पूरा हो जाने की उपलब्धि को दर्शाया गया है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि स्टेकहोल्डर्स की बेहतर भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने के लिए अनेक साल से देश के निर्माण में कंपनी के निरंतर प्रयासों और पहलों का प्रमाण है।

जोमैटो का घाटा बढ़कर 359 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली। खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी सुविधा उपलब्ध कराने वाले मंच जोमैटो का एकीकृत शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बढ़कर 359.7 करोड़ रुपए हो गया। अधिक खर्चों के कारण कंपनी का घाटा बढ़ा है। जोमैटो ने सोमवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में कंपनी को 134.2 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी की एकीकृत परिचालन आय बीते वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में बढ़कर 1211.8 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 692ण. करोड़ रुपए थी। कंपनी का आलोच्य तिमाही में कुल खर्च भी बढ़कर 1701.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह एक साल पहले की इसी अवधि में 885 करोड़ रुपए था। वहीं, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए जोमैटो का एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 1222.5 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 816.4 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि बीते वित्त वर्ष में उसकी परिचालन आय भी बढ़कर 4192.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 1993.8 करोड़ रुपए थी।

एनआरएआई के साथ बैठक करेगा उपभोक्ता मंत्रालय

रेस्त्रांओं द्वारा ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलने का मामला

नई दिल्ली। रेस्तरांओं द्वारा ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूलने की मिली शिकायतों के बाद उपभोक्ता मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। सूत्रों की माने तो 2 जून को इस मामले को लेकर उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ एनआरएआई के साथ बैठक करेगा। इस तरह की शिकायतों मिल रही हैं कि रेस्तरांओं द्वारा ग्राहकों को जबरन सेवा शुल्क देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह बैठक इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर उठाई गई है। मंत्रालय ने यह बैठक कई मीडिया रिपोर्टों और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद यह बैठक बुलाई है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने भी एनआरएआई अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि रेस्तरां और भोजनालय अपने उपभोक्ताओं से गलत तरीके से सेवा शुल्क ले रहे हैं जबकि इस तरह के किसी भी शुल्क का संग्रह स्वैच्छिक है। मंत्रालय दो जून की बैठक में रेस्तरां द्वारा किसी अन्य शुल्क या उसकी आड़ में सेवा शुल्क को बिल में शामिल करने के मामले में उपभोक्ता शिकायतों पर चर्चा करेगा।

उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं रेस्तरां संचालक

सचिव ने पत्र में यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह शुल्क रेस्तरां मनमाने तरीके से उच्च दरों पर तय करते हैं। उपभोक्ता जब बिल राशि से इस तरह के शुल्क को हटाने का अनुरोध करते हैं, तो उपभोक्ताओं को गुमराह कर इस तरह के शुल्कों को वैध ठहराने का प्रयास किया जाता है। पत्र में कहा गया है, यह मुद्दा उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर प्रभावित करता है और यह उनके अधिकारों का भी मामला है, इसलिए विभाग ने इसे बारीकी और विस्तार से जांचने का फैसला किया है।

शेयर बाजार में गिरावट

मुंबई। वैश्विक बाजार की तेजी के बावजूद ऊंचे भाव पर धातु, बेसिक मैटेरियल्स, ऊर्जा, हेल्थकेयर, दूरसंचार, यूटिलिटीज, रियल्टी और तेल एवं गैस समेत 11 समूहों में हुई बिकवाली से सोमवार को कारोबार के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। धातु समूह में आठ प्रतिशत से अधिक के भूचाल ने शेयर बाजार में दबाव बनाया, जिससे बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 37.78 अंक फिसलकर 54288.61 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी 51.45 अंक टूटकर 16214.70 अंक पर आ गया। इस दौरान छोटी और मझौली कंपनियों में अधिक बिकवाली हुई, जिससे बीएसई का मिडकैप 0.26 प्रतिशत गिरकर 22,449.32 अंक और स्मॉलकैप 0.64 प्रतिशत उतरकर 26,182.06 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई के 11 समूह लुढ़क गए। धातु समूह में सबसे अधिक 8.33 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा बेसिक मैटेरियल्स 4.08 फीसदी की गिरावट रही।

धातु कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट

सरकार द्वारा इस्पात विनिर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर निर्यात शुल्क लगाए जाने के बाद सोमवार को धातु कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट आई। जिंदल स्टील का शेयर सबसे अधिक 17 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आ गया। बीएसई में जिंदल स्टील के शेयर 17.40 प्रतिशत, जेएसडब्ल्यू स्टील में 13.20 प्रतिशत तथा टाटा स्टील के शेयर में 12.53 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा एनएमडीसी के शेयर में 12.44 प्रतिशत, सेल में 10.96 प्रतिशत, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 3.65 फीसदी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 3.42 फीसदी और वेदांता के शेयर में 2.77 प्रतिशत का नुकसान रहा। इस दौरान धातु सूचकांक भी 8.33 प्रतिशत का गोता लगाकर 17655.22 अंक पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील

आइसक्रीम की कीमत 10 फीसदी तक बढ़ी

कोरोना काल के बाद इस साल बिक्री में उछाल

नई दिल्ली। भीषण गर्मी में आइसक्रीम की ठंडक लेना महंगा हो गया है। कोरोना काल के 2 सालों बाद इस साल आइसक्रीम की मांग में इजाफा हुआ है, जबकि आपूर्ति घटी है। जिसके चलते कंपनियों ने आइसक्रीम के दाम 8 से 10 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती गर्मी की वजह से साल 2019 के मुकाबले पिछले तीन महीनों में आइसक्रीम की बिक्री में 45 फीसदी तक का उछाल आया है। जिसके चलते कंपनियों ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल आइसक्रीम का उत्पादन भी 30 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2022 में ज्यादा मांग की वजह से इंडस्ट्री के 9000 करोड़ रुपए के अनुमान की बजाय 11000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने की उम्मीद है। यह बात 80 प्राइवेट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को लीड करने वाले एसोसिएशन ने कही। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे शहरों में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खरीदी गई।

जल्द सेवा शुरू करेगी आकाश

नई दिल्ली। नई एयरलाइन आकाश एयर ने सोमवार को कहा कि वह जून के मध्य तक अपना पहला बोइंग 737 मैक्स विमान प्राप्त करने और जुलाई तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की राह पर है। एयरलाइन ने सोमवार को अमेरिका के पोर्टलैंड में बोइंग विनिर्माण कंपनी से अपने पहले मैक्स विमान की तस्वीरें जारी कीं, जो आपूर्ति के लिए तैयार है। बयान में एयरलाइन ने जून के मध्य तक भारत में अपना पहला विमान प्राप्त होने और जुलाई 2022 तक देश में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। एयरलाइन की मार्च 2023 के अंत तक देश में घरेलू मार्गों पर 18 विमान उड़ाने की योजना है। आकाश एयर बड़े शहरों से टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए उड़ानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एयरलाइन जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला और विमानन दिग्गज विनय दुबे तथा आदित्य घोष द्वारा समर्थित है। उसे वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने के लिए अगस्त 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पिछले साल अगस्त के अंत में बोइंग 737 मैक्स विमान को हरी झंडी दी थी। इसके बाद, आकाश एयर ने 26 नवंबर 2021 को बोइंग के साथ 72 मैक्स विमानों की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयरलाइन ने कहा

जुलाई तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद

आईपीएल एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी और लखनऊ सुपर जाइंट्स में होगी कड़ी टक्कर

कोलकाता (एजेंसी)।

आईपीएल के 15वें सत्र में बुधवार को होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) और लखनऊ सुपर जाइंट्स आमने-सामने होंगे। आरसीबी इस सत्र में अपने खेल से ज्यादा किस्तम के भरोसे यहां तक पहुंची हैं और अब उसका लक्ष्य किसी भी प्रकार से यह मैच जीतना रहेगा। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के फार्म में आने से भी टीम का हौंसला बढ़ा है। विराट ने इस सत्र में अब तक केवल दो अर्धशतक लगाये हैं पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम लीग मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ ही अपने फार्म में आने का संकेत दिया है। विराट ने जिस प्रकार अंतिम लीग मुकाबले में 54 गेंद में 73 रन बनाए उससे उनके हौंसले बुलंद हैं अब उनका लक्ष्य अगले मैच में भी बड़ा स्कोर बनाना रहेगा।

आरसीबी को प्लेऑफ में जगह भी किस्मत के सहारे ही मिली है। अंतिम लीग मुकाबले में जीत के बाद भी उसकी राह कठिन थी पर दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस के हाथों हार से उसे अंतिम चार में प्रवेश मिल गया। आरसीबी को अगर लखनऊ पर

जीत चाहिये तो विराट के अलावा कप्तान फाफ डुप्लेसी , ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक को बड़ी पारियां खेलनी होंगी। कार्तिक ने जिस प्रकार इस सत्र में 'फिनिशर' की भूमिका निभाई है उन्हें उसे बरकरार रखना होगा। इसके अलावा गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, वानिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल को प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा। टीम के पास तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी हैं हालांकि वह अब तक इस सत्र में असफल रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हुआ है। आरसीबी ने अब तक एक बार भी खिताब नहीं जीता है और ऐसे में डु प्लेसी उसे जीत दिलाना चाहेंगे। तीन आईपीएल फाइनल खेल चुकी आरसीबी के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं पर वह अंतिम चरण में बिखर जाती है। अब देखना है कि शांत तरीके से कप्तानी करने वाले डु प्लेसी उसे जीत दिला पाते हैं या नहीं।

नई पिच पर होने वाले नॉकआउट मैच में आरसीबी के गेंदबाजों का सामना करना नई टीम लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। आरसीबी को इस मैच में कार्तिक से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कार्तिक को भी आईपीएल में ही अच्छे प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया में फिर जगह मिली है ऐसे में वह अपने चयन को सही साबित करना चाहेंगे। इस बल्लेबाज ने अब तक 14 पारियों में 287 रन बनाये हैं वह नौ बार नाबाद रहे और उनका स्ट्राइक रेट 191.33 रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के पास युवा तेज गेंदबाज आवेश खान और मोहसिन खान हैं जिनका सामना करना आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्हें लखनऊ के दुष्मंता चामीरा और जैसन होल्डर जैसे अनुभवी गेंदबाजों का भी सामना करना होगा। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो यह जिम्मेदारी कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटोन डिकॉक पर रहेगी। इन दोनो ने अबतक शानदार प्रदर्शन करते हुए एक हजार से अधिक रन बनाये हैं। इसमें केकेआर के खिलाफ 210 रन की सबसे बड़ी सलामी साझेदारी भी शामिल है। टीम की कमजोर कड़ी यह है कि उसके पास मध्यक्रम और निचले क्रम में दीपक हुड्डा को छोड़कर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो इस सत्र में सफल रहा हो। मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पंड्या, आयुष बदोनी और होल्डर मध्यक्रम में रन नहीं बना पाये हैं। ऐसे में शीर्ष बल्लेबाजों के विफल होने पर टीम की बल्लेबाजी ढ़ह सकती है।

फ्रेंच ओपन: मेदवेदेव आसान जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंचे

पेरिस (एजेंसी)।

रूस के दूसरे वरीय दानिल मेदवेदेव ने आसान जीत के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। अमेरिकी ओपन चैंपियन मेदवेदेव ने अर्जेन्टीना के फाकुंडो बाग्निस को सीधे सेट में 6-2, 6-2, 6-2 से हराया।

लगभग दो महीने पहले हर्निया की सर्जरी कराने के बाद मेदवेदेव की यह पहली जीत है। पिछले हफ्ते सर्जरी के बाद वापसी करते हुए उन्हें जिनेवा ओपन के पहले दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फ्रेंच ओपन के पहले दौर में लगातार चार बार शिकस्त झेलने वाले मेदवेदेव पिछले साल रोलां गैरो पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे थे।

योग और ध्यान से मिली एकाग्रता से गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मिली यॉर्कर डालने में महारत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत के बायें हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा कि योग और ध्यान के जरिये उन्होंने एकाग्रता पाई जिससे परफेक्ट यॉर्कर डालने में मदद मिली जिसके दम पर वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिये भारत की टी20 टीम में जगह बना सके। 23 वर्ष के इस तेज गेंदबाज ने स्वीकार किया कि आईपीएल में उन्हें सफलता मिली लेकिन सब कुछ उन्हें अपनी मेहनत से अर्जित करना पड़ा। अपनी मर्जी के हिसाब से यॉर्कर डालने का हुनर कुदरती भले ही हो लेकिन आईपीएल से पहले अपने निजी कोच जसवंत राय के साथ उन्होंने इसे निखारा। योग और ध्यान से भी दबाव के पलों में शांत बने रहने में मदद मिली।

अर्शदीप ने पीटीआई से कहा ,'' ध्यान से दिमाग स्पष्ट हो जाता है। दबाव के हालात में इस स्पष्टता का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे पलों में शांत रहने से काफी मदद मिलती है।'' आईपीएल में काफी समय बिताने के बाद घर लौटकर अर्शदीप आराम कर रहे हैं लेकिन नौ जून से दिल्ली में शुरू हो रही श्रृंखला के लिये उन्हें भारतीय टीम से जुड़ना है। इस सत्र में उन्होंने नयी गेंद की बजाय पुरानी गेंद से अधिक गेंदबाजी की क्योंकि पंजाब किंग्स ने आखिरी ओवरों में उन पर काफी भरोसा किया। टीम द्वारा सत्र से पहले बरकरार रखे गए दो खिलाड़ियों में शामिल अर्शदीप ने डैथ ओवरों में 7 . 31 की औसत से गेंदबाजी की।

महिला टी20 क्रिकेट: पूजा की शानदार गेंदबाजी से सुपरनोवाज जीती

पुणे (एजेंसी)।

पूजा वस्त्राकर के शानदार प्रदर्शन से सुपरनोवाज टीम ने महिला टी20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में ट्रेलब्लेजर्स को 49 रनों से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपरनोवाज ने इस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 163 रन बनाए जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रेलब्लेजर्स की टीम 9 विकेट पर 114 रन ही बना पाई। इस मैच में पूजा और अन्य गेंदबाजों ने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पूजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। एलाना किंग ने 2 विकेट लिए जबकि मेघना सिंह और सोफी एक्लेस्टोन ने एक-एक विकेट लिया। इस मैच में 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रेलब्लेजर्स को

सलामी बल्लेबाज हेली मैथ्यूज और कप्तान स्मृति मंधाना ने अच्छी शुरुआत दिलायी पर हेली को पूजा ने पांचवें ओवर में आउट कर टीम को पहला झटका दिया। हेली 18 रन बनाकर आउट हुईं। पूजा ने इसके बाद कप्तान मंधाना को भी पेवेलियन भेज दिया। मंधाना ने 34 रन बनाए। वहीं इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्ज ने पारी को संभालने का प्रयास किया पर वह 24 रन बनाकर मेघना सिंह का शिकार बनी। जेमिमा ने 24 रन बनाए। अंतिम बल्लेबाज रेणुका सिंह ने 14 रन बनाए और वह नाबाद रहीं। वहीं इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए सुपरनोवाज की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। वहीं हरलीन देओल ने 35 और ओपनर डिएंड्रा डोटिन ने 32 रन बनाये। सुपरनोवाज ने शुरुआत अच्छी करते हुए पावरप्ले में 58 रन बनाये। डोटिन ने 32 रन बनाए। प्रिया पूनिया ने 22 रन बनाये। हरलीन देओल ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान हरमनप्रीत के साथ 37 रन बनाये। वहीं ट्रेलब्लेजर्स की ओर से हेली मैथ्यूज ने तीन जबकि सलमा खातून ने 2 विकेट लिए।

छेत्री फिट हुए , जोर्डन के खिलाफ मैत्री मैच खेलेंगे

नई दिल्ली । भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की छह महीने बाद वापसी हुई है। छेत्री जोर्डन के खिलाफ 28 मई को दोहा में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में खेलेंगे। छेत्री अक्टूबर में सैफ चैम्पियनशिप फाइनल में नेपाल के खिलाफ हुए मैच के बाद से ही चोटिल होने के कारण टीम से बाहर थे। अब वह पूरी तरह से फिट हो गये हैं ओर खेलने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमक ने कोलकाता में अभ्यास शिविर के दौरान 25 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसमें छेत्री के अलावा ईशान पंडित को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं वी पी सुहैर और रहीम अली को फिट नहीं होने के कारण टीम से जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम 25 मई को दोहा रवाना होगी और मैत्री मैच के बाद 30 मई को स्वदेश लौटकर एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर की तैयारियां करेगी।

भारतीय टीम इस प्रकार है

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, लक्ष्मीकांत कट्टीमणि, अमरिंदर सिंह

डिफेंडर : राहुल भेके, आकाश मिश्रा, हरमनजोत सिंह खाबरा, रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, शुभाशीष बोस, प्रितम कोताल ।

मिडफील्डर: जैकसन सिंह, अनिरूद्ध थापा, ग्लान मार्टिंस, ब्रेंडन फर्नांडिस, रित्विक दास, उदांता सिंह, यासिर मोहम्मद, सहल अब्दुल समाद, सुरेश वांगजाम, आशिक कुरूनियन, लिस्टन कोलासो ।

फॉरवर्ड : ईशान पंडित , सुनील छेत्री, मनवीर सिंह ।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में काउंटी सत्र का लाभ मिलेगा: पुजारा

नई दिल्ली । भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के अनुभवों का लाभ उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट में मिलेगा। पुजारा ने काउंटी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम ससेक्स की ओर से डिवीजन दो के पांच मैच में दो दोहरे शतक और दो शतक की मदद से 720 रन बनाए हैं। इसी कारण उनकी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है।

पुजारा ने कहा, 'मुझे खुशी है कि मुझे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम में जगह मिली है। हाल में काउंटी में मेरे प्रदर्शन पर ध्यान के कारण यह संभव हुआ।' उन्होंने कहा, 'काउंटी मुकाबलों के दौरान क्रीज पर समय बिताने के बाद मेरा मानना है कि मुझे इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में इसका लाभ मिलेगा।' पुजारा ने कहा, ' मैं हमेशा की तरह ही दौरे से पहले अच्छी तैयारी और ट्रेनिंग को लेकर उत्सुक हूं तथा उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम में योगदान देना जारी रखूंगा।' गौरतलब है कि भारतीय टीम कोरोना संक्रमकण के कारण पिछले साल पांचवां टेस्ट नहीं खेल पायी थी जो अब बर्मिंघम में एक से पांच जुलाई तक खेला जाएगा। वहीं पिछले कुछ समय में खराब फॉर्म को देखते हुए पुजारा को इस साल की शुरुआत में ही भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था पर ससेक्स की ओर से शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने टीम में वापसी की है।

रोहित-कोहली के फॉर्म पर खुलकर बोले सौरव गांगुली, वह भी इंसान हैं, गलतियां होंगी

मुबई (एजेंसी)।

भारत में क्रिकेट का खुमार बढ़-चढ़कर रहता है। भारतीय क्रिकेट टीम को लोगों से जबरदस्त समर्थन में मिलता है। क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खूब फॉलो भी करते हैं। वर्तमान में देखें तो देश में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर गजब का क्रेज है। हालांकि यह बात भी सच है कि दोनों खिलाड़ी फिलहाल लय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोहित शर्मा के लिए इस बार का इंडियन प्रीमियर लीग अच्छा नहीं गया। उनकी टीम मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे नीचे रही। जबकि रोहित शर्मा का भी प्रदर्शन काफी खराब रहा। रोहित शर्मा ने 14 पारियों में 19.14 की औसत से 268 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी महज 120 का रहा। विराट कोहली के लिए भी इस बार का आईपीएल कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि आखिरी के कुछ मुकाबलों में उनके बल्ले से रन जरूर आए। अब तक विराट कोहली ने 13 पारियों में महज 236 रन बनाए हैं। दोनों खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म होना भारत के लिए चिंता की बात है।

भारत के इन दोनों खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि रोहित के फॉर्म पर कहा कि हर कोई से

इंसान है गलतियां होंगी। लेकिन कप्तान के रूप में रोहित का रिकॉर्ड उत्कृष्ट है। पाँच आईपीएल खिताब, एशिया कप विजेता, उसने जहां भी कप्तानी की है, वह जीता है। कप्तान के रूप में उसका रिकॉर्ड शानदार है। गलतियाँ होंगी क्योंकि वे सभी इंसान हैं। कोहली के लिए भी यह सत्र बेहद निराशाजनक रहा। दोनों का समर्थन करते हुए, गांगुली ने कहा कि वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि वे रनों बनाना शुरू करेंगे। वे इतना क्रिकेट खेलते हैं कि कई बार वे फॉर्म गंवा बैठते है। कोहली ने पिछले मैच बहुत अच्छा खेला, खासकर जब आरसीबी के लिए इसकी जरूरत थी।

पंत और मलिक पर बयान

आईपीएल में ऋषभ पंत भी बल्ले से अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। विकेट के पीछे भी डीआरएस को लेकर उनके फैसले की आलोचना हुई लेकिन गांगुली ने इस विकेटकीपर बल्लेबाज का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंत की तुलना धोनी से मत करिये। धोनी के पास काफी अनुभव है। उसने आईपीएल, टेस्ट और एकदिवसीय मिलाकर 500 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है। धोनी के साथ पंत की तुलना सही नहीं है। गांगुली ने सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वह अपनी फिटनेस बरकरार रखते है तो लंबे समय के साथ राष्ट्रीय टीम के साथ रहेंगे।

भारत के प्रज्ञानानंदा मेल्टवाटर चैम्पियंस शतरंज टूर के सेमीफाइनल में पहुंचे

चेन्नई । भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेल्टवाटर चैम्पियंस शतरंज टूर चेसेबल मास्टर्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। प्रज्ञानानंदा ने चीन के वेइ यि को 2.5- 1.5 से हराकर इस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनायी है। प्रज्ञानानंदा का मुकाबला अब सेमीफाइनल में नीदरलैंड के अनीश गिरी से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का सामना दूसरे सेमीफाइनल में चीन के डिंग लिरेन से होगा। गिरी ने नॉर्वे के आर्यन तारी और कार्लसन ने स्पेन के डेविड एंतोन गुजारो को हराया था। वहीं लिरेन ने अजरबैजान के शखरियार मामेदियारोव को पराजित किया। प्रज्ञानानंदा ने छठे दौर में कार्लसन को हराया था। वह अनीश, कार्लसन और लिरेन के बाद प्रारंभिक दौर में चौथे स्थान पर थे। वहीं दो अन्य भारतीय खिलाड़ी पी हरिकृष्णा और विदित गुजराती हार के साथ ही शीर्ष 8 में नहीं पहुंच पाये।

सरफराज के भाई मुशीर को मुंबई रणजी टीम में मिली जगह

मुम्बई । मुम्बई ने रणजी ट्राफी के नॉकआउट मुकाबले के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। इस टीम में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज सरफराज खान के छोटे भाई ऑलराउंडर मुशीर खान को शामिल किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को टीम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण शामिल नहीं किये गये हैं। मुम्बई टीम पृथ्वी शॉ की कप्तानी में 6 जून से उत्तराखंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। टीम में शामिल मुशीर ने अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में 9 मैचों में 67 की औसत से 670 रन बनाए और 32 विकेट भी लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए। मुशीर ने मुंबई को कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया था। मुंबई अंडर 25 टीम के लिए उन्होंने 3 मैचों में 401 रन बनाए। जिसमें मणिपुर के खिलाफ 267 रन की पारी भी शामिल है। मुशीर नेशनल क्रिकेट एकेडमी जोनल कैंप के लिए चुने जाने के बाद अभी सूरत में अभ्यास कर रहे हैं। इस क्रिकेटर ने अपने चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं चयनकर्ताओं और एमसीए का आभारी हूं।

एशिया कप: जीत से चूका भारत

आखिरी मिनट में गोल दाग पाकिस्तान ने 1-1 की बराबरी पर रोका

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप हॉकी में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। भारत ने इससे मैच में शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। लेकिन आखिरी मिनट में पाकिस्तान की ओर से गोल दागकर मैच को बराबरी पर खत्म किया गया। तीसरे क्वार्टर यानी कि 45 मिनट की खेल तक टीम इंडिया पाकिस्तान से 1-0 से आगे चल रही थी। लेकिन चौथे क्वार्टर के आखिरी मिनट में पाकिस्तान की ओर से अब्दुल राणा ने पेनल्टी कार्नर के जरिए गोल करके स्कोर को 1-1 की बराबरी पर कर दिया। हालांकि भारत ने गोल के खिलाफ रेफरल जरूर लिया था। लेकिन वह भी बेकार चला गया। भारत एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। हालांकि इस बार भारत के लिए अभियान की शुरुआत ड्रॉ से हुई है। भारत और पाकिस्तान की ओर से दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं किया जा सका। हालांकि दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को गोल करने के कई मौके मिले। लेकिन भारतीय डिफेंडर ने शानदार बचाव किया। भारतीय खिलाड़ी लगातार इस मुकाबले में अटैक करते रहे। भारत की ओर से पहले ही क्वार्टर में एक गोल दागा गया था। सेल्वम कार्थी ने पहले क्वार्टर के नौवें मिनट में शानदार गोल दागा था। इस बार भारतीय खेमे में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। टीम की कप्तानी अनुभवी बीरेंद्र लाकड़ा कर रहे हैं। 2017 में जब हॉफी का एशिया कप खेला गया था, तब भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। भारत को अब पूरे में अपना अगला मुकाबला जापान के खिलाफ खेलना है।

धोनी को क्रिकेट का भगवान मानती है किरण नवगिरे, इस खास वजह से शुरू किया क्रिकेट खेलना

पुणे। किरण नवगिरे ने महेंद्र सिंह धोनी के प्रति अपने अपार प्रेम को जाहिर किया है। वह उन्हें क्रिकेट का भगवान मानती हैं। महाराष्ट्र की इस धाकड़ बल्लेबाज ने कहा, 'मैं धोनी की तरह लंबे छक्के लगाना चाहती थी और इसी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। देश के साथ-साथ मेरे लिए भी बहुत कुछ बदल सा गया जब धोनी ने (2011) विश्व कप जीतने के लिए वह छक्का लगाया था।' 11 वर्षों बाद नवगिरे अपनी बल्लेबाजी के दम पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में संपन्न हुई महिला टी20 लीग में नागालैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने सर्वाधिक 35 छक्के लगाए। इसके अलावा उन्होंने 54 चौकों की मदद से कुल 525 रन बनाए। इस दौरान वह एक टी20 मैच में 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। साथ ही अपनी पार्ट टाइम ऑफ स्पिन से उन्होंने सात विकेट झटके।

पीएम मोदी और बाइडेन ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया

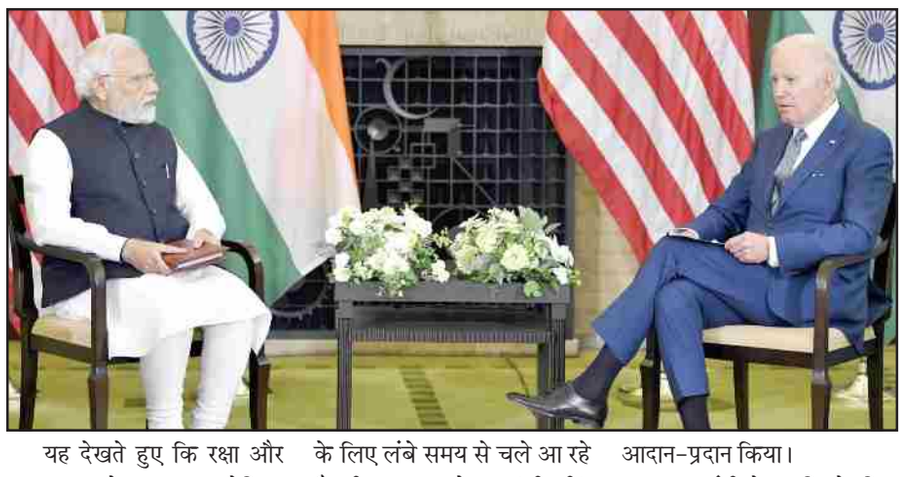

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया है, जो यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई, बुनियादी ढांचा आदि में भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाता है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मंगलवार को टोक्यो में मुलाकात की। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और उनके बीच उपयोगी बातचीत हुई। बैठक के ठोस परिणाम निकले जिससे द्विपक्षीय साझेदारी और गहरी होगी तथा उसे गति मिलेगी।

यह बैठक दोनों नेताओं के बीच नियमित उच्चस्तरीय बातचीत की निरंतरता का प्रतीक है। दोनों नेताओं की इससे पहले सितंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी में व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी और उसके बाद जी20 और सीओपी26 शिखर सम्मेलन में बातचीत हुई थी। हाल ही में 11 अप्रैल, 2022 को उनके बीच वर्चुअल बातचीत हुई थी।

भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडा में सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका परिणामोन्मुखी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) पर पहल की शुरुआत की। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सह-नेतृत्व में, आईसीईटी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी/6जी, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की सरकारों के बीच शिक्षा और उद्योग में घनिष्ठ संबंध स्थापित होंगे।'

यह देखते हुए कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत-अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, दोनों पक्षों ने चर्चा की कि वे सहयोग को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में निर्माण करने के लिए अमेरिकी उद्योग को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया, जो दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी हो सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने बढ़ते सहयोग को आगे ले जाते हुए, भारत और अमेरिका ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने के लिए लंबे समय से चले आ रहे वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वीएपी) को 2027 तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप टीकों और संबंधित तकनीकों का विकास हुआ।

दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया, जो पारस्परिक लाभ का हो सकता है।

दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के शुभारंभ का स्वागत किया और कहा कि भारत संबंधित राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक लचीले और समावेशी आईपीईएफ को आकार देने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि नेताओं ने अपनी उपयोगी बातचीत जारी रखने और भारत-अमेरिका साझेदारी को उच्च स्तर पर ले जाने के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

सामाजिक रूप से भारत को तबाह करने के मिशन पर बीजेपी : ओवैसी

'पीएम मोदी का 56 इंच का सीना हो गया गायब'

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। अपने बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भी चर्चा में रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके उन्होंने भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस हिंदुत्व वैचारिक परियोजना से कमजोर और नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इतना ही नहीं उन्होंने पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि हमारे पास एक पीएम साहब हैं, जिनका 56 इंच का सीना गायब हो गया है।

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एक मजबूत समावेशी भारत के लिए है जहां सभी भारतीयों के अधिकार सुरक्षित हैं और संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए यह न्याय की लड़ाई है।

मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ है। यही मौलिक जिम्मेदारी है जिसके लिए इसे चुना गया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे अर्थव्यवस्था का प्रबंधन भी नहीं कर सकते है जो कि मंदी में है। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक रूप से भाजपा भारत को तबाह करने के मिशन पर है।

चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सरकार के पास वहां भेजने के लिए डोजर नहीं है। इस सरकार में चीन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि चीनी सैनिक लद्दाख में हमारे क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि हमारे पास एक पीएम साहब हैं, जिनका 56 इंच का सीना गायब हो गया है।

इससे पहले ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगलकाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा है, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन ये बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं? उनके इस पोस्ट के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है।

ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री सरमा के मदरसे को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई थी। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिस्वा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, असम में 18 लोग मारे गए हैं और 7 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभद्र टिप्पणियों में व्यस्त हैं। उन्होंने आगे कहा, जब संघी ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, तब मदरसे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। इस्लाम के अलावा कई मदरसे विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं।

'वंदे मातरम्' को मिले राष्ट्रगान के बराबर सम्मान, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करके मांग की गई है कि राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्र गान 'जन गण मन' के बराबर सम्मान दिया जाए। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत खूब गाया जाता था। कोर्ट से मांग की गई है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे की स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में रोज राष्ट्रगान के साथ 'वंदे मातरम' भी गाया या बजाया जाए।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि 24 जनवरी 1950 को मद्रास कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन किया जाए। याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि वे वंदे मातरम गाएं और देश की अखंडता को बनाए रखें। इसके अलावा सरकार का भी यह दायित्व है कि वह जन गण मन और वंदे मातरम को समान रूप से प्रमोट करें।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से किसी की भावनाएं आहत होने का सवाल नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसे सम्मान देने की बात कही थी। याचिका में कहा गया, 'जन गण मन में एक राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए भावनाएं व्यक्त की गई हैं वहीं वंदे मातरम में देश के चरित्र की बात की गई है इसलिए दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए।'

याचिका में कहा गया है कि कई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब वंदे मातरम गाने पर आपत्ति जाहिर की जाती है। लेकिन यह सभी भारतीयों का दायित्व है कि वंदेमातरम जब भी गाया जाए तो उसका सम्मान करें। जब भारत को स्वतंत्रता दिलाने लिए आंदोलन चल रहा था तब वंदे मातरम पूरे देश का विचार और मोटो बन गया था। लोग वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकालते थे।

योगी 2.0 सरकार का पहला बजट : संकल्प पत्र की कई योजनाएं शामिल, गुरुवार को होगा पेश

लखनऊ, 24 मई (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 26 मई गुरुवार को सदन में प्रस्तुत करेगी। इसे पहले ही बजट के माध्यम से सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल अधिकांश योजनाओं और वादों को पूरा करने की कोशिश करती नजर आएगी। बजट का खाका खींचा जा चुका है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर होने का अनुमान है।

वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। इस धनराशि में से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा। राज्य का यह अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट होगा। बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को भी वित्त विभाग सक्रिय रहा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार के बजट में इस बार संकल्प पत्र की छाप नजर आएगी।

संकल्प पत्र में शामिल प्रदेश सरकार की 70 फीसदी से अधिक घोषणाओं व योजनाओं को बजट में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट से समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ नया दिखेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। चार महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया था ताकि जरूरी खर्चे का प्रबंध हो सके।

इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए बजट का प्रबंध हो सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रख सकती है।

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं।

प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना भी बजट में शामिल किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा।

मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस ने टास्क फोर्स का किया गठन

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से पहले तीन समितियों के गठन की घोषणा की। टास्क फोर्स-2024 ने एआईसीसी कार्यालय में बैठक की और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।

राजनीतिक मामलों का समूह कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्तियों सहित प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देगा। राजनीतिक मामलों के समूह के संसदीय बोर्ड या एक कोर समूह के रूप में कार्य करने की संभावना है, क्योंकि असंतुष्टों ने पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने के लिए संसदीय बोर्ड के पुनरुद्धार की मांग की थी।

राहुल के साथ, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सलाह को अधिक महत्व दिया जाएगा। राहुल के अहम सहयोगी के सी वेणुगोपाल को भी दोनों समितियों में रखा गया है।

टास्क फोर्स 2024 तक चुनाव प्रबंधन की देखभाल करेगी, जिसका मतलब है कि यह प्रियंका गांधी पर अधिक निर्भर होगी, जो पूर्व आईपीएसी सदस्य सुनील कानूनगोलू के साथ चुनावी मुद्दों पर प्रेरक शक्ति होगी, जबकि पी चिदंबरम और जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ सदस्य गठबंधन की देखभाल कर सकते हैं।

ऐसे मुद्दे जो यूपीए और समान विचारधारा वाले दलों के भीतर सबसे बड़ी बाधा हैं। अहमद पटेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस के पास संभावित सहयोगियों से बात करने के लिए एक अनुभवी हाथ नहीं है। टास्क फोर्स-2024 में मुकुल वासनिक, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला सदस्य हैं।

पार्टी के एक बयान में कहा गया है, टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य को संगठन, संचार और मीडिया, आउटरीच, वित्त और चुनाव प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य सौंपे जाएंगे। उनके पास नामित टीमें होंगी जिन्हें बाद में अधिसूचित किया जाएगा। टास्क फोर्स उदयपुर 'संकल्प' घोषणा और छह समन्वय समूहों की रिपोर्ट पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

कांग्रेस ने उदयपुर में अपने 'चिंतन शिविर' के दौरान तय किए गए तीन समितियों का गठन किया है - राजनीतिक मामलों के समूह, टास्क फोर्स -2024 और 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए एक समिति।

कांग्रेस के बयान में कहा गया है, उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक राजनीतिक मामलों के समूह का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की जाएगी।

हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, एससी ने झारखंड हाई कोर्ट पर छोड़ा फैसला

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से मंगलवार को कहा कि वह उस जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने संबंधी प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले सुनवाई करे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कुछ सेल कंपनियों के लेन-देन और खनन पट्टों की कथित मंजूरी की जांच का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने 13 मई के अपने आदेश में खुद कहा था कि वह पहले इस बात पर विचार करेगा कि शिव कुमार शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं और फिर वह याचिका में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर गौर करेगा।

पीठ ने कहा, ''हमारा विचार है कि हाई कोर्ट रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने संबंधी प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले विचार करेगा और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।''

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

राज्यों के अधिकार ठी आर्थिक संकट खड़ा कर रही है मोदी सरकार : सीएम स्टालिन

सलेम, 24 मई (एजेन्सी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्यों के अधिकार छीनकर सभी राज्य सरकारों पर एक तरह का आर्थिक संकट थोप रही है। वह सलेम में पिछले एक साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए एक पार्टी बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्टालिन ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से वित्त और कर से संबंधित सभी अधिकार छीन लिए हैं और एक तरह का आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है।

स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ियन मॉडल, जो ज्ञानवापी मामले और संबंधित दावों व प्रतिद्वंद्वी दलों के प्रति-दावों का परोक्ष संदर्भ प्रतीत होता है, वह कुछ नष्ट नहीं करेगा बल्कि निर्माण करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह मॉडल किसी को विभाजित नहीं करेगा बल्कि एकजुट करेगा। भाजपा का नाम लिए बिना स्टालिन ने कहा कि कुछ लोग 'अध्यात्मवाद' के आधार पर बनी सरकार पर लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वे यहां कोई खामी नहीं ढूंढ पा रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके की सरकार ने कभी भी किसी की आस्था और श्रद्धा के लिए अवरोध नहीं खड़ा किया है और यही रुख जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार थी जिसने राज्य में मंदिरों की 2500 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां उन्हें वापस दिलवाई थीं। हाल ही में, तमिलनाडु भाजपा ने एक शैव मठ की पालकी की रस्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। बाद में, इस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें जनता की सेवा न कर पाएं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को अभी भी केंद्र की ओर से 21,761 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र को ईंधन पर उतना कम करना चाहिए जितना साल 2014 में इसके सत्ता संभालने के बाद बढ़ा है। पिछले साल हमारी सरकार ने पेट्रोल पर तीन रुपये कर घटाया था, जिससे 1160 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।

आप से नहीं संभल रहा है पंजाब, पकड़े जाने पर हटाया स्वास्थ्य मंत्री को : गौरव भाटिया

नई दिल्ली, 24 मई (एजेन्सी)। पंजाब के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाकर वाहवाही लूटने पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि जहां-जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, वहां-वहां अपने आप भ्रष्टाचार पहुंच जाता है और आम आदमी पार्टी से पंजाब संभल नहीं पा रहा है।

भाजपा ने कांग्रेस और आप दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की जनता और ज्यादा त्रस्त हो गई है क्योंकि भ्रष्टाचारी (कांग्रेस) पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन अब महा-भ्रष्टाचारी पार्टी (आप) सत्ता में आ गई है।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 6 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 20 दिन में उन्होंने पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है तो जिस भ्रष्टाचार को आप ने 20 दिन में खत्म कर दिया था क्या उसका पुनर्जन्म भी आप सरकार ने ही कराया है?

भाजपा प्रवक्ता ने आप की सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि, आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। आप की पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी निकले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 2 प्रदेश, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी। यानी 100 प्रतिशत करप्शन रेट अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं।

भाटिया ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार को आये हुए 68 दिन ही हुए हैं और सरकार के कामकाज को देखकर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी से पंजाब संभल नहीं रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री को हटाने पर वाहवाही लूटने के प्रयासों पर निशाना साधते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि, पंजाब के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, आप के लिए कमीशन और घूसखोरी कर रहे थे। लेकिन जब वह पकड़े गए तो उन्हें मजबूरी में हटते हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com